सांध्य दैनिक

श्रीकंचनपथ

RNI. Reg. No. CHHHIN/2009/30534

डाक पंजीयन क्रं.-छ.ग./दुर्ग/1000000029/2026-28

लीपा पोती नहीं सिर्फ सच

वर्ष- 17 अंक - 266 | www.shreekanchanpath.com | संस्थापक एवं प्रेरणास्रोत- स्व. श्रीमती रजनी अग्रवाल | भिलाई, गुरूवार 09 जुलाई 2026 | पृष्ठ 8- मूल्य 1/-

खास-खबर

महादेव ऐप का संचालक सौरभ चंद्राकर ओमान में गिरफ्तार

रायपुर। महादेव ऑनलाइन सट्टा ऐप

के मुख्य आरोपी सौरभ चंद्राकर को ओमान में गिरफ्तार किया गया है। उसने फर्जी इंडोनेशियाई पासपोर्ट के जरिए ओमान में प्रवेश किया था। इसी मामले में रॉयल ओमान पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि सौरभ चंद्राकर पहले संयुक्त अरब अमीरात में रह रहा था। उसकी गिरफ्तारी इंटरपोल के रेड नोटिस के आधार पर की गई है, जिसे भारतीय जांच एजेंसियों के अनुरोध पर जारी किया गया था। गिरफ्तारी के बाद भारत सरकार उसे वापस लाने की प्रक्रिया में जुट गई है। इसके लिए ओमान सरकार से प्रत्यर्पण (भारत भेजने) की कानूनी प्रक्रिया पूरी की जा रही है। फिलहाल सौरभ चंद्राकर को मस्कट के अल खौद डिटेंशन सेंटर में रखा गया है। उसने अपनी तरफ से केस लड़ने के लिए वकीलों की टीम भी रखी है। वहीं, ओमान में फर्जी पासपोर्ट और अवैध तरीके से प्रवेश करने के मामले की जांच जारी है।

छत्तीसगढ़ में अगले 4 दिन भारी बारिश का अलर्ट

रायपुर। छत्तीसगढ़ में तीन दिन के ब्रेक के बाद मानसून फिर एक्टिव हो गया है। मौसम विभाग ने अगले चार दिनों तक कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान जताया है। उत्तर छत्तीसगढ़ के एक-दो इलाकों में गरज-चमक और बिजली गिरने का अलर्ट भी है। हालांकि, अब तक प्रदेश में सामान्य से 17त्न कम बारिश हुई है। तापमान की बात करें तो रायपुर 32 डिग्री के साथ सबसे गर्म रहा, जबकि पेंड्रारोड में न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग के मुताबिक 10 जुलाई बादल छाए रहेंगे। गरज-चमक के साथ बारिश होने की संभावना है। शहर का अधिकतम तापमान 31एष्ट और न्यूनतम तापमान 25एष्ट के आसपास रहने का अनुमान है।

बस ने हेड कॉन्स्टेबल को रौंदा कई मीटर घिसटती रही बाइक

सरगुजा। जिले के राष्ट्रीय राजमार्ग-343 पर लुचकी घाट के पास सोमवार रात हुए भीषण सड़क हादसे में पुलिस लाइन में पदस्थ हेड कॉन्स्टेबल श्रीराम लकड़ा की दर्दनाक मौत हो गई। तेज रफ्तार बस की टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि उनकी बाइक बस के अगले हिस्से में फंस गई और वे कई मीटर तक सड़क पर घिसटते चले गए। गंभीर चोटों के कारण उनकी मौके पर ही मौत हो गई। हादसा सोमवार रात करीब 8 बजे हुआ। अंबिकापुर की ओर आ रही बस ने बाइक सवार हेड कॉन्स्टेबल को ठोकर मार दी जिससे उसकी मौके पर मौत हो गई।

तीजन बाई के नाम पर अब हर साल मिलेगा पंडवानी कलाकारों को सम्मान

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। छत्तीसगढ़ की लोकसंस्कृति को वैश्विक पहचान दिलाने वाली पंडवानी की महान लोकगायिका स्वर्गीय डॉ. तीजन बाई की स्मृति को हमेशा के लिए संजोने की दिशा में राज्य सरकार ने कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। रायपुर में आयोजित श्रद्धांजलि समारोह में संस्कृति मंत्री राजेश अग्रवाल ने कहा कि डॉ. तीजन बाई का योगदान केवल छत्तीसगढ़ ही नहीं, बल्कि पूरे देश की सांस्कृतिक धरोहर है और उनकी विरासत को संरक्षित करने के लिए सरकार ठोस कदम उठा रही है। सरकार ने घोषणा की है कि पंडवानी कला के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाले कलाकारों को अब हर वर्ष 'डॉ. तीजन बाई राज्य अलंकरण सम्मान' से सम्मानित किया जाएगा। इसका उद्देश्य लोककला के संरक्षण के साथ नई पीढ़ी के कलाकारों को प्रोत्साहित करना है। इस मौके पर मंत्री ने डॉ. तीजन बाई के परिजनों को एक लाख रुपये की आर्थिक सहायता भी प्रदान की। उन्होंने कहा कि सरकार कलाकारों और उनकी सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षण के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है।

गनियारी को 'कलाग्राम' के रूप में विकसित किया जाएगा

डॉ. तीजन बाई के पैतृक गांव गनियारी को 'कलाग्राम' के रूप में विकसित किया जाएगा। यहां लोककला, पंडवानी और पारंपरिक संस्कृति से जुड़ी गतिविधियों को बढ़ावा दिया जाएगा, ताकि यह स्थान कला और संस्कृति का प्रमुख केंद्र बन सके। इसके अलावा, डॉ. तीजन बाई की प्रस्तुतियों का अभिन्न हिस्सा रहा उनका ऐतिहासिक तंबूरा अब रायपुर स्थित महंत घासीदास स्मारक संग्रहालय में संरक्षित किया जाएगा। इसे आम लोगों के लिए प्रदर्शित किया जाएगा, जिससे उनकी कला और जीवन यात्रा को नजदीक से जानने का अवसर मिलेगा। कार्यक्रम में वक्ताओं ने कहा कि डॉ. तीजन बाई ने अपने अद्वितीय गायन और अभिनय से पंडवानी को अंतरराष्ट्रीय मंच तक पहुंचाया। राज्य सरकार की ये पहलें उनकी स्मृतियों को संरक्षित करने के साथ-साथ आने वाली पीढ़ियों को अपनी लोक संस्कृति और परंपराओं से जोड़ने का महत्वपूर्ण माध्यम बनेंगी।

छत्तीसगढ़ में 1 अप्रैल से शुरू होगा नया शैक्षणिक सत्र, स्कूल शिक्षा विभाग ने जारी किया आदेश

■ **अगले साल से लागू होगी नई व्यवस्था, मई और जून में रहेंगी गर्मी की छुट्टियां**

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। छत्तीसगढ़ में अगले शैक्षणिक सत्र से बड़ा बदलाव होने जा रहा है। अब प्रदेश के स्कूल 16 जून के बजाय 1 अप्रैल 2027 से खुलेंगे। इस संबंध में स्कूल शिक्षा विभाग ने आदेश जारी कर दिया है। विभाग का कहना है कि इस बदलाव से स्टूडेंट्स को पढ़ाई के लिए ज्यादा समय मिलेगा, समय पर सिलेबस पूरा कराया जा सकेगा और बोर्ड परीक्षाओं के परिणामों में भी सुधार आएगा।

स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव डॉ. कमलप्रीत सिंह द्वारा जारी आदेश के अनुसार, प्रदेश में अब शैक्षणिक सत्र 1 अप्रैल से 31 मार्च तक प्रभावी रहेगा। यह व्यवस्था सीबीएसई सहित अन्य राष्ट्रीय शिक्षा बोर्डों की तर्ज पर लागू की जाएगी। नई व्यवस्था के तहत 1 अप्रैल से स्कूल

खुलेंगे। इसी दौरान प्रवेश प्रक्रिया पूरी की जाएगी और स्टूडेंट्स को पुस्तकें, यूनिफॉर्म और साइकिल दिया जाएगा। इसके बाद 1 मई से 15 जून तक गर्मी की छुट्टियां रहेंगी।

फिलहाल, प्रदेश में स्कूल 16 जून से खुलते हैं। स्कूल खुलने के बाद कई दिनों तक नए छात्रों का प्रवेश, किताबें, स्कूल ड्रेस (यूनिफॉर्म), साइकिल और दूसरी सरकारी सुविधाएं बांटने का काम चलता रहता है। इसकी वजह से नियमित पढ़ाई देर से शुरू होती है और कई स्कूलों में जुलाई तक पढ़ाई प्रभावित रहती है।

सीबीएसई की तर्ज पर होगा नया शिक्षा सत्र

स्कूल शिक्षा विभाग का मानना है कि अब तक सीबीएसई स्कूलों और सीजी बोर्ड स्कूलों के शैक्षणिक कैलेंडर में करीब ढाई महीने का अंतर रहता था। सीबीएसई स्कूल अप्रैल से पढ़ाई शुरू कर देते हैं, जबकि सीजी बोर्ड स्कूल जून के मध्य में खुलते हैं। इस अंतर के कारण प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी, बोर्ड परीक्षा की रणनीति और पाठ्यक्रम पूरा करने में भी फर्क दिखाई देता था। अब दोनों व्यवस्थाओं के बीच यह अंतर काफी हद तक समाप्त हो जाएगा।

जानिए क्या बदलेगा?

- 1 अप्रैल 2027 से नया शैक्षणिक सत्र शुरू होगा।
- सरकारी और सीजी बोर्ड से संबद्ध निजी स्कूलों में यह व्यवस्था लागू होगी।
- अप्रैल में ही प्रवेश प्रक्रिया, किताब, यूनिफॉर्म और साइकिल वितरण होगा।
- मई और जून में पहले की तरह ग्रीष्मकालीन अवकाश रहेगा।
- जुलाई से नियमित रूप से पढ़ाई आगे बढ़ेगी।
- वार्षिक परीक्षा के परिणाम 31 मार्च तक जारी करने का लक्ष्य रहेगा।

महापौर-पार्षदों से टकराव के बाद भिलाई निगम आयुक्त का ट्रांसफर

श्रीकंचनपथ न्यूज

भिलाई। छत्तीसगढ़ के प्रशासनिक महकमे में फेरबदल किया गया। राज्य सरकार ने 8 आईएएस और 19 राज्य प्रशासनिक सेवा अधिकारियों (पीसीएस) का तबादला किया है। भिलाई नगर निमग में जन प्रतिनिधियों से टकराव के बाद आयुक्त राजीव कुमार पाण्डेय को भी हटा दिया गया है। अब उनकी पदस्थापना अपर संचालक, उच्च शिक्षा संचालनालय नवा रायपुर में हुई है।

भिलाई नगर निगम के तत्कालीन आयुक्त राजीव कुमार पाण्डेय का तबादला महज प्रशासनिक निर्णय नहीं माना जा रहा। जनवरी में महापौर ने मुख्य सचिव को पत्र लिखकर आयुक्त पर करोड़ों रुपए के कार्य बिना सामान्य सभा की मंजूरी स्वीकृत करने और वित्तीय अनियमितताओं के आरोप लगाए थे।

मार्च में कांग्रेस और भाजपा के पार्षदों ने एकजुट होकर आयुक्त के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दिया था। वहीं दूसरी ओर भाजपा पार्षदों ने भी नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साव से शिकायत की कि कामकाज ठप होने से जनता के बीच जाना मुश्किल हो रहा है। मंत्री द्वारा जांच के निर्देश दिए जाने के बाद आयुक्त को हटाने की प्रक्रिया तेज हो गई थी।

इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने छत्तीसगढ़ में ईवी चार्जिंग नेटवर्क को मिलेगा बूस्ट

■ **राज्य सरकार लॉन्च करेगी ऐप, बैठक में लिया गया निर्णय**

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को तेज़ी से बढ़ाने का फैसला लिया है। मंत्रालय में सचिव सह-परिवहन आयुक्त एस प्रकाश की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय बैठक हुई। बैठक में परिवहन विभाग, सभी आरटीओ, डीटीओ, ऊर्जा विभाग, एचपीसीएल, बीपीसीएल, एलओसीएल, जिओ -बीपी, ईवी निर्माता और विशेषज्ञ मौजूद रहे।

अभी अलग-अलग कंपनियों के अलग-अलग एप हैं, जिससे उपभोक्ताओं को परेशानी होती है। सरकार अब राज्य स्तर पर एकीकृत प्लेटफॉर्म/एप बनाएगी। भारत सरकार भी यूनिवर्सल ईवी चार्जिंग एप ला रही है। चिप्स के जरिए ऊर्जा विभाग पहले ही पायलट एप पर काम कर रहा है। केंद्र की पीएम ई-ड्राइव योजना के तहत चार्जिंग स्टेशन लगाने पर वित्तीय सहायता और छत्तीसगढ़ ईवी नीति-2022 के प्रोत्साहनों पर विस्तार से चर्चा हुई।

सभी जिलों के आरटीओ डीटीओ को अपने क्षेत्र में चार्जिंग स्टेशनों के लिए जगह चिन्हित करने और एनओसी की प्रक्रिया तेज करने के निर्देश दिए गए।

एचपीसीएल, बीपीसीएल, एलओसीएल, जिओ -बीपी के निर्माताओं ने राज्य में लगे और प्रस्तावित चार्जिंग स्टेशनों की जानकारी दी और आगे विस्तार की योजना बताया। सचिव सह-परिवहन आयुक्त ने कहा कि ईवी चार्जिंग का मजबूत नेटवर्क बनाना और लोगों को समय पर जानकारी देना जरूरी है। इससे हरित परिवहन को बढ़ावा मिलेगा और प्रदूषण कम होगा। छत्तीसगढ़ सरकार का लक्ष्य राज्यभर में आसान और सुलभ चार्जिंग सुविधा देकर ज्यादा से ज्यादा लोगों को ईवी अपनाने के लिए प्रेरित करना है।

उरला फैक्ट्री हादसे के बाद सख्त कार्रवाई, मृतक श्रमिकों के परिजनों को 30-30 लाख का मुआवजा

■ **उरला हादसे पर प्रशासन का त्वरित एक्शन, कारखाने की समस्त विनिर्माण गतिविधियां बंद**

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। ग्राम बेन्द्री उरला औद्योगिक क्षेत्र के पास बुधवार को मेसर्स 3-डी इनोवेशन कारखाने में एक गंभीर औद्योगिक दुर्घटना हुई। हादसे में तीन श्रमिकों की मौत हो गई। हादसे के बाद सरकार ने त्वरित कार्रवाई करते हुए कारखाने की समस्त विनिर्माण गतिविधियां बंद कर दी हैं। वहीं मृतकों के परिजनों को 30-30 लाख रुपए मुआवजा भी दिया जाएगा।

बता दें जानकारी के अनुसार मेसर्स 3-डी इनोवेशन के फेरो एलॉयज डिवीजन में संचालित फर्नेस में लांसिंग कार्य के दौरान ऑक्सीजन सिलेंडर में अचानक भीषण विस्फोट होने से कार्यरत तीन श्रमिकों अरुण पाण्डेय, लाल सिंह एवं कमल सिंह की मृत्यु हो गई। दुर्घटना की सूचना प्राप्त होते ही औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा विभाग द्वारा

तत्काल घटनास्थल पहुंचकर दुर्घटना स्थल का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान घटनास्थल का विस्तृत परीक्षण कर आवश्यक साक्ष्य लिए गए, फोटोग्राफ एवं विडियोग्राफ लिए गए तथा कारखाना प्रबंधन एवं श्रमिकों से प्रारंभिक पूछताछ कर दुर्घटना के कारणों की जांच प्रारंभ की गई।

कंपनी प्रबंधक को निर्देश

प्रारंभिक जांच के आधार पर एवं श्रमिकों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्यदशा संहिता, 2020 की धारा 38(1)(ए) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कारखाना परिसर में संचालित समस्त प्रकार की विनिर्माण गतिविधियों को तत्काल प्रभाव से आगामी आदेश तक प्रतिबंधित कर दिया गया है। इस संबंध में कारखाने के अधिभोगी एवं प्रबंधक को प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया है।

दुर्घटना के कारणों की विस्तृत जांच जारी

औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा विभाग द्वारा यह भी निर्देशित किया गया है कि प्रतिबंधात्मक आदेश की अवधि में कारखाने में नियोजित सभी श्रमिकों को नियमानुसार देय वेतन एवं अन्य भत्तों का भुगतान निर्धारित समय पर सुनिश्चित किया जाए। विभाग के प्रयासो से कारखाना प्रबंधन द्वारा प्रत्येक मृतक श्रमिक के परिजनों को 30 - 30 लाख रूपए की तत्काल आर्थिक सहायता राशि देने की सहमति दी गयी। औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा विभाग द्वारा दुर्घटना के कारणों की विस्तृत जांच की जा रही है। जांच प्रतिवेदन एवं उपलब्ध तथ्यों के आधार पर नियमानुसार आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।

संपादकीय

ताजमहल का मामला

अदालतों को काल्पनिक बातों की जांच-पड़ताल में अपना वक्त जाया नहीं करना चाहिए

साल 2015 में, एक दीवानी मुकदमे में ताजमहल को हिंदू मंदिर घोषित करने की मांग की गई थी। इस अप्रैल में जब आगरा की एक निचली अदालत ने उक्त स्मारक का सर्वे करने के लिए एक एडवोकेट कमिश्नर नियुक्त करने की याचिकाकर्ताओं की मांग को ठुकरा दिया, तो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ताओं की चुनौती पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) से जवाब मांगा है। अदालत यह जवाब इस बात को तय करने से पहले मांग रही है कि निचली अदालत के इनकार को बरकरार रखा जाए या नहीं। कानूनी स्थिति को अलग रखें तो भी, यह मामला ओछा और खीझ पैदा करने वाला है। आज यह विचार कि ताजमहल 'मूल रूप से' एक हिंदू मंदिर था, पुरुषोत्तम नागेश ओक की 20वीं सदी के आखिर की रचनाओं से जुड़ा है। पेशेवर इतिहासकारों और पुरातत्वविदों ने बार-बार उनके दावों को खारिज किया है, क्योंकि वे अटकलों पर आधारित भाषाई तर्कों और बिना सबूत वाले ऐतिहासिक दावों पर टिके हैं। दूसरी तरफ़ शाहजहां द्वारा ही ताजमहल बनवाए जाने के सबूत उस दौर के वृत्तांतों, प्रशासनिक रिकॉर्ड, यूरोपीय यात्रियों के विवरणों, वास्तुकला के इतिहास और पुरातत्व से मिलते हैं। किसी भी पुरातात्विक अध्ययन में ताजमहल के नीचे मध्यकालीन हिंदू मंदिर होने का कोई सबूत नहीं मिला है। भले ही एएसआई ने पहले हलफनामों में कहा है कि कुछ कमरे इसलिए बंद हैं क्योंकि वे बनावट के लिहाज से कमजोर हैं, लेकिन मंदिर होने की बात मानने वालों का आरोप है कि उनमें हिंदू मूर्तियां छिपी हुई हैं। भारतीय जनता पार्टी के एक नेता ने 2022 में एक जनहित याचिका भी दायर की थी जो सफल नहीं रही और 2024 में कार्यकर्ताओं ने 'गंगाजल' चढ़ाने की कोशिश की। सही ऐतिहासिक, राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक हालात होने पर, छद्म-इतिहास (श्यूडोहिस्ट्री) से उपजा कोई विचार अपनी शुरुआत के काफी समय बाद भी बना रह सकता है।

> अदालत यह जवाब इस बात को तय करने से पहले मांग रही है कि निचली अदालत के इनकार को बरकरार रखा जाए या नहीं। कानूनी स्थिति को अलग रखें तो भी, यह मामला ओछा और खीझ पैदा करने वाला है। आज यह विचार कि ताजमहल 'मूल रूप से' एक हिंदू मंदिर था, पुरुषोत्तम नागेश ओक की 20वीं सदी के आखिर की रचनाओं से जुड़ा है। पेशेवर इतिहासकारों और पुरातत्वविदों ने बार-बार उनके दावों को खारिज किया है, क्योंकि वे अटकलों पर आधारित भाषाई तर्कों और बिना सबूत वाले ऐतिहासिक दावों पर टिके हैं। दूसरी तरफ़ शाहजहां द्वारा ही ताजमहल बनवाए जाने के सबूत उस दौर के वृत्तांतों, प्रशासनिक रिकॉर्ड, यूरोपीय यात्रियों के विवरणों, वास्तुकला के इतिहास और पुरातत्व से मिलते हैं। किसी भी पुरातात्विक अध्ययन में ताजमहल के नीचे मध्यकालीन हिंदू मंदिर होने का कोई सबूत नहीं मिला है। भले ही एएसआई ने पहले हलफनामों में कहा है कि कुछ कमरे इसलिए बंद हैं क्योंकि वे बनावट के लिहाज से कमजोर हैं, लेकिन मंदिर होने की बात मानने वालों का आरोप है कि उनमें हिंदू मूर्तियां छिपी हुई हैं।

अभी चल रहा मामला ज्ञानवापी और मथुरा विवादों जैसा ही है, जहां निष्पक्ष सर्वे की मांग का इस्तेमाल असल में राजनीतिक नैरेटिव को बदलने या नए सिरे से पेश करने के लिए किया गया था। अदालतों के पास ऐसी याचिकाओं को खारिज करने का अधिकार है जिनमें कार्रवाई का कोई ठोस आधार नहीं बताया गया हो, क्योंकि वे इतिहास से जुड़ी बातों की जांच करने वाले आयोग नहीं हैं और उन्हें किसी भी काल्पनिक ऐतिहासिक परिकल्पना को निगरानी वाली जांच का पर्याप्त आधार नहीं मानना चाहिए। इसी तरह, दीवानी प्रक्रिया को ऐसे दावों पर दोबारा मुकदमा चलाने की इजाजत नहीं देनी चाहिए जिनका कोई ठोस सबूत न हो। समय के साथ सभी प्रमुख स्मारकों में कुछ न कुछ बदलाव होते रहते हैं और नई चीजें जुड़ती रहती हैं, लेकिन विरासत के जानकार स्मारक के विकास को समझने और उसकी पहचान को पूरी तरह से बदलने के बीच के फर्क को मानते हैं।

ताजमहल 1983 में यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल (वर्ल्ड हेरिटेज साइट) घोषित हुआ। इसकी पहचान को फिर से तय करने की बार-बार की जा रही कोशिशों से इस स्मारक की देखरेख को लेकर भारत की छवि पर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर गलत असर पड़ सकता है और इलाके की पर्यटन पर आधारित अर्थव्यवस्था भी बिगड़ सकती है। हो सकता है कि ठीक से जांच-पड़ताल के बाद हाईकोर्ट निचली अदालत के आदेश से सहमत हो जाए, लेकिन इस दावे पर जरा भी ध्यान देने की जरूरत नहीं है। याचिकाकर्ताओं ने कोई नया सबूत पेश नहीं किया है, जबकि विरासत से जुड़ी संस्थाओं पर मनगढ़ंत बातों से विवाद खड़ा करने के लिए लगातार कानूनी दबाव डाला जा रहा है।

स्वच्छ ऊर्जा के उपयोग को प्रोत्साहन: विकासशील अर्थव्यवस्थाओं की प्रगति का व्यावहारिक रास्ता

श्रीपाद नाइक

वैश्विक स्तर पर बढ़ती अनिश्चितता, ऊर्जा की बढ़ती मांग और जलवायु से जुड़ी गंभीर चुनौतियों के इस दौर में, अंतरराष्ट्रीय समुदाय को ऐसी ऊर्जा प्रणालियों का निर्माण करने की जरूरत है जो स्वच्छ व अपेक्षाकृत अधिक सुरक्षित, सस्ती एवं भरोसेमंद होने के साथ-साथ विकासशील अर्थव्यवस्थाओं की विकास संबंधी जरूरतों तथा आर्थिक आकांक्षाओं के अनुरूप भी हों।

स्वच्छ ऊर्जा दरअसल ऊर्जा सुरक्षा, औद्योगिक विकास और दीर्घकालिक विकास की दृष्टि से तेजी से अहम होती जा रही है। यह ईंधन बाजार में आने वाले उतार-चढ़ाव से पैदा होने वाले जोखिमों को कम कर सकती है, ऊर्जा को अपेक्षाकृत अधिक सुलभ बना सकती है, रोजगार सृजित कर सकती है, घरेलू उद्योगों को मजबूत कर सकती है और देश को अपेक्षाकृत अधिक सुदृढ़ बना सकती है। फिर भी, स्वच्छ ऊर्जा की दिशा में आगे बढ़ने के रास्ते एक जैसे नहीं हो सकते। इन रास्तों को राष्ट्रीय परिस्थितियों, उपलब्ध संसाधनों और विकास की प्राथमिकताओं के हिसाब से निर्धारित किया जाना चाहिए।

इसी बिंदु पर विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के बीच आपसी सहयोग महत्वपूर्ण हो जाता है। ब्रिक्स के सदस्य देशों के बीच बेहतर सहयोग से स्वच्छ ऊर्जा को अपनाने की प्रक्रिया में तेजी लाने के साथ-साथ ऊर्जा सुरक्षा, स्थिरता और समावेशी विकास के साझा लक्ष्यों को भी आगे बढ़ाया जा सकता है। भारत का अपना अनुभव यह बताता है कि स्वच्छ ऊर्जा की शुरुआत लोगों से ही होनी चाहिए।

पिछले दशक में, प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना (सौभाग्य) के तहत लगभग 28.6 मिलियन घरों को बिजली के कनेक्शन दिए गए। इससे सभी तक बिजली पहुंचाने का काम आगे बढ़ा और ग्रामीण व कम सुविधा वाले इलाकों में लोगों के जीवन स्तर में सुधार हुआ। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाई) के तहत महिलाओं को 105 मिलियन से अधिक एलपीजी कनेक्शन दिए गए। इससे खाना पकाने के साफ-सुथरे तरीकों को बढ़ावा मिला, घर में सेहत बेहतर हुई और कठिन श्रम का बोझ कम हुआ।

ये पहल एक महत्वपूर्ण सिद्धांत को रेखांकित करती हैं: स्वच्छ ऊर्जा को अपनाने को केवल स्थापित मेगावाट या जोड़ी गई क्षमता के आधार पर नहीं मापा जा सकता, बल्कि इससे पैदा हुए अवसरों, सुदृढ़ हुई आजीविका और बेहतर हुए जीवन स्तर के आधार पर भी मापा जाना चाहिए।

लोगों को प्राथमिकता देने वाले इस दृष्टिकोण के साथ-साथ बड़े पैमाने पर काम और सहयोगी बुनियादी ढांचे की भी जरूरत है। भारत की स्वच्छ ऊर्जा की कहानी में नवीकरणीय ऊर्जा अहम हो गई है। लेकिन इसकी सफलता इसे समर्थन प्रदान करने वाली प्रणालियों पर निर्भर करती है। सौर और पवन ऊर्जा को तेजी से अपनाया जा सकता है, लेकिन इनकी पूरी क्षमता का लाभ तभी मिल पाएगा जब पारेषण (ट्रांसमिशन), वितरण (डिस्ट्रीब्यूशन), भंडारण (स्टोरेज) और ग्रिड प्रबंधन एकसाथ मिलकर काम करें।

भारत ने स्वच्छ ऊर्जा के विस्तार में सहायता प्रदान करने वाली प्रणालियों को मजबूत करने की दिशा में उल्लेखनीय प्रगति की है। पारेषण संबंधी बुनियादी ढांचे (ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर) का निरंतर विस्तार हुआ है। इसके साथ-साथ ऊर्जा के भंडारण (एनर्जी स्टोरेज) और ग्रिड की सुदृढ़ता (ग्रिड फ्लेक्सिबिलिटी) के क्षेत्र में भी निवेश बढ़ा है। वितरण (डिस्ट्रीब्यूशन) संबंधी सुधारों और उन्नत ग्रिड तकनीक को अपनाने से एक ऐसी बेहतर एवं भरोसेमंद ऊर्जा प्रणाली बनाने में मदद मिली है, जो नवीकरणीय ऊर्जा की बढ़ती हिस्सेदारी को समन्वित करने में सक्षम है।

भारत की गैर-जीवाश्म ईंधन पर आधारित क्षमता अब 288 गीगावॉट से अधिक हो गई है। बड़े पैमाने की परियोजनाओं के अलावा, वितरित नवीकरणीय ऊर्जा (डीआरई) प्रणालियां - जैसे कि रूफटॉप सोलर, सोलर पंप, मिनी-ग्रिड और माइक्रो-ग्रिड - ग्रामीण और कम सुविधा वाले इलाकों में स्वच्छ ऊर्जा को और अधिक सुलभ बना रही हैं। ये प्रणालियां सिंचाई, कोल्ड स्टोरेज, स्कूलों, हेल्थकेयर सेंटरों तथा स्थानीय व्यवसायों को मदद पहुंचाने के साथ-साथ ग्रामीण आजीविका और स्थानीय आर्थिक सुदृढ़ता को भी बढ़ावा दे रही हैं।

भारत की 'पीएम सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना' बड़े पैमाने पर इस दृष्टिकोण को दर्शाती है। इस योजना से अब तक लगभग 4 मिलियन परिवारों को लाभ हुआ है, जिससे उपभोक्ता अपेक्षाकृत अधिक विकेन्द्रीकृत एवं भागीदारी वाली ऊर्जा प्रणाली में योगदान देने वाले बन पाए हैं।

हालांकि, स्वच्छ ऊर्जा के विस्तार में वित्त पोषण सबसे अहम तत्वों में से एक बना रहेगा। कई विकासशील देशों में नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं, लेकिन इन संभावनाओं को बड़े पैमाने पर लागू करने तथा बैंक से ऋण पाने योग्य परियोजनाओं में बदलने हेतु सस्ती और दीर्घकालिक पूंजी की जरूरत होती है।

आने वाले वर्षों में नवीकरणीय ऊर्जा, वितरण संबंधी बुनियादी ढांचा, ग्रिड के आधुनिकीकरण, भंडारण प्रणाली और कम ऊर्जा खर्च करने वाली तकनीकों में निवेश बेहद जरूरी होगा। न्यू डेवलपमेंट बैंक जैसे संस्थान वित्त पोषण, तकनीक संबंधी साझेदारी और क्षमता विकास के जरिए विकासशील देशों की मदद करने में अहम भूमिका निभा सकते हैं।

स्वच्छ ऊर्जा से जुड़ी तकनीकों के लिए सुदृढ़ एवं विविधतापूर्ण आपूर्ति श्रृंखला बनाना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के लिए सुरक्षित, सस्ती और भरोसेमंद ऊर्जा प्रणालियां सुनिश्चित करने हेतु मैन्यूफैक्चरिंग, तकनीक, नवाचार और आपूर्ति श्रृंखला के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाना जरूरी होगा।

अब जबकि ब्रिक्स की भारत की अध्यक्षता आगे बढ़ रही है, सहयोग की एक ऐसी भविष्योन्मुखी रूपरेखा को मजबूत करने का अवसर है जो सामर्थ्य, बड़े पैमाने पर काम करने की क्षमता, विश्वसनीयता, तकनीक की सुलभता, सुदृढ़ आपूर्ति श्रृंखला और सतत विकास का समर्थन करे।

चुनौती सिर्फ स्वच्छ ऊर्जा की क्षमता को बढ़ाने की ही नहीं, बल्कि ऐसे ऊर्जा प्रणाली के निर्माण की भी है जो सबके लिए सुलभ, किफ़ायती एवं भरोसेमंद होने के साथ-साथ दीर्घकालिक आर्थिक विकास और मानव विकास को कायम रखने में सक्षम हों।

(लेखक विद्युत राज्यमंत्री हैं)

महसूस होने वाला तापमान बने गर्मी का पैमाना

प्रोफेसर पूर्णेंदु रंजन

दरअसल, मौजूदा उमस भरी गर्मी एक चेतावनी है। जब हवा का तापमान कुछ और कहे और इंसान की त्वचा कुछ और महसूस करे, तो सार्वजनिक नीतियों को इंसान की त्वचा का साथ देना होगा। साधारण थर्मामीटर पर निर्भरता के बजाय हीट इंडेक्स आधारित नीतिगत व प्रशासनिक ढांचा तैयार करना जरूरी है।

मानसून के आगमन से पहले के दिनों में कदम बाहर निकालते ही हवा दमघोंटू महसूस होने लगती है। हवा सिर्फ गर्म नहीं है; इसमें एक ऐसा भारीपन, सघनता और ठहराव है मानो वायुमंडल का वजन बढ़ गया हो और हमारी त्वचा को दबा रहा हो। दोपहर होते-होते, सामान्य वेदर ऐप हवा का तापमान 39 या 40 डिग्री सेल्सियस दिखा सकता है, जो देखने में शायद सहनीय लगे। लेकिन शरीर को यह तापमान 49-50 डिग्री सेल्सियस के समान महसूस होता है। यह कोई वहम नहीं; 'हीट इंडेक्स' की वह डरावनी वास्तविक तस्वीर है जो साबित करती है कि हमारे पारंपरिक मौसम वैज्ञानिक पैमाने इंसानी शरीर के जलवायु संकट को मापने में बुनियादी रूप से विफल हो रहे हैं।

दशकों से, भारत में सार्वजनिक प्रशासन और आपातकालीन हीट प्रोटोकॉल केवल एक ही आंकड़े से संचालित हो रहे हैं: एक साधारण थर्मामीटर पर आंका जाने वाला 'ड्राई-बल्ब' तापमान। यदि राजस्थान के सूखे मैदानी इलाकों में पारा 45 डिग्री से. छू जाता है, तो उसे आधिकारिक तौर पर 'लू' (हीटवेव) घोषित कर दिया जाता है। लेकिन मौजूदा उमस भरी गर्मी कहीं अधिक कपटपूर्ण थर्मोडायनामिक सिद्धांत पर काम कर रही है। मानसून की देरी के कारण दक्षिण-पश्चिमी हवाएं आती हैं, तो ह्यूमिडिटी 60-70 प्रतिशत तक बढ़ जाती है। मानव शरीर खुद को ठंडा रखने के लिए पसीने का वाष्पीकरण करता है। त्वचा से पसीना वाष्पीकृत होता है जो अपने साथ शरीर की आंतरिक ऊष्मा को बाहर ले जाता है। बहरहाल, जब आसपास की हवा पहले से ही नमी से पूरी तरह संतृप्त हो—एक भीगे हुए स्पंज की तरह—तो वाष्पीकरण की यह प्रक्रिया ठप हो जाती है। शरीर का आंतरिक अनुकूलन तंत्र काम करना बंद कर देता है, और उसका तापमान घातक सीमाओं की ओर बढ़ने लगता है। यह स्थिति हमें 'वेट-बल्ब तापमान' की चरम सीमा के खतरनाक रूप से करीब ले आती है जो कि मानव शरीर द्वारा झेली जा सकने वाली संयुक्त गर्मी और आर्द्रता की अंतिम सीमा है। अमेरिका के 'पेंसिल्वेनिया स्टेट हीट प्रोजेक्ट' के हालिया चिकित्सा अनुसंधान के मुताबिक, मानव शरीर मात्र 31 डिग्री सेल्सियस के वेट-बल्ब स्तर पर ही अपने आंतरिक तापमान पर नियंत्रण खोना शुरू कर देता है। इस उमस भरे प्रहार का सबसे बड़ा खतरा है कि यह हमारी वर्तमान प्रशासनिक व्यवस्थाओं के लिए संरचनात्मक रूप से अदृश्य बना रहता है। जून के अंत और अब जुलाई के शुरू में महानगरों में 'हीट इंडेक्स' 51 से 53 डिग्री पार कर गया। ड्राई-बल्ब तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास था, तो भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) कठोर नियामक मानदंडों के कारण अक्सर आधिकारिक तौर पर हीटवेव की घोषणा नहीं कर सका। इससे श्रमिकों की परेशानी की अनदेखी हुई। 'लू' घोषित नहीं होती, इसलिए श्रम प्रवर्तन एजेंसियां निर्माण श्रमिकों, डिलीवरी ब्वॉयज और कृषि मजदूरों के लिए दोपहर के विश्राम की अवधि निर्धारित नहीं करतीं। इन कामकाजी लोगों को 50 डिग्री की दहकती भट्ठी जैसी स्थिति में खटना पड़ता है। वहीं 'हीटस्ट्रोक' के मामलों में स्वास्थ्य प्रणालियां अक्सर उमस के दौर में हताहतों की संख्या कम आंकती हैं। यदि भारत को ऐसे युग में जीवित रहना है जहां 'महसूस होने वाला' तापमान नियमित रूप से 50 डिग्री सेल्सियस के आंकड़े को छू रहा हो, तो हमारी जलवायु अनुकूलन रणनीतियों को क्रांतिकारी बदलाव से गुजरना होगा। आईएमडी और राज्य आपदा प्रबंधन अधिकारियों को

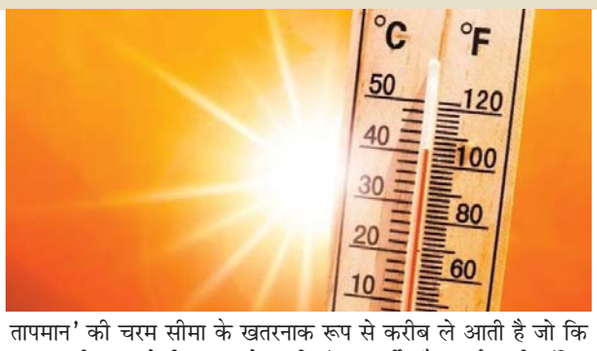

सार्वजनिक स्वास्थ्य चेतावनियों, स्कूलों की छुट्टियों और श्रम नियमों के निर्धारण के कानूनी पैमाने के रूप में ड्राई-बल्ब थर्मामीटर को हटाकर आधिकारिक तौर पर 'कंपोजिट हीट रिस्क इंडेक्स' (संयुक्त ऊष्मा जोखिम सूचकांक) को लागू करना चाहिए। 65 फीसदी आर्द्रता वाले 40 डिग्री सेल्सियस के दिन को भी प्रशासनिक रूप से उतनी ही गंभीरता मिले, जितनी 47 डिग्री सेल्सियस वाले शुष्क दोपहर को।

इस दमघोंटू गर्मी के प्रति आम उपभोक्ताओं की स्वाभाविक प्रतिक्रिया अधिक से अधिक निजी हाई-पावर सप्लिट एसी खरीदने की होती है। लाखों निजी एसी बेहद गर्म हवा सीधे तंग सड़कों पर छोड़ते हैं, जिससे 'अर्बन हीट आइलैंड' का प्रभाव गहरा हो जाता है। यह शहरी गरीबों के लिए सार्वजनिक रास्तों को 'थर्मल डेथ ट्रैप' बना देता है जो एसी नहीं खरीद सकते। भारत को इसके वैश्विक संरचनात्मक विकल्पों की ओर देखना चाहिए, जैसे फ्रांस का भूमिगत 'क्लाइमस्पेस' नेटवर्क या गुजरात के 'गिफ्ट सिटी' में हमारा अपना स्वदेशी मॉडल। हमें कूलिंग को एक सेंट्रलाइज्ड पब्लिक यूटिलिटी के रूप में अपनाना होगा—यानी ऐसे 'डिस्ट्रिक्ट कूलिंग सिस्टम' जो इंसुलेटेड पाइपों के जरिए ठंडे पानी को पूरे वाणिज्यिक और आवासीय क्षेत्रों में घुमाकर ठंडा रख सकें।

भवन नियमों को शीशे और कंक्रीट के उन ढांचों से दूर हटना होगा जो विशाल ग्रीनहाउस जाल की तरह काम करते हैं। 'ऊर्जा संरक्षण भवन कोड' लागू कर इमारतों में प्रकाश परावर्तित करने वाली ठंडी छतें, क्रॉस-वेंटिलेशन के रास्ते और खोखली इंसुलेटेड ईंटों का उपयोग अनिवार्य किया जाए। यह अंदरूनी तापमान को 5 डिग्री तक कम कर सकता है, जिससे रहने के लिए एसी पर निर्भरता कम हो जाएगी।

जलवायु परिवर्तन हमारे जीवन को सीधे नहीं, बल्कि विभिन्न कारकों को आपस में मिलाकर तेजी से प्रभावित कर रहा है। जब हवा का तापमान कुछ और कहे और इंसान की त्वचा कुछ और महसूस करे, तो हमारी सार्वजनिक नीतियों को हमेशा इंसान की त्वचा का साथ देना होगा। यह समय साधारण थर्मामीटर को विदा करने और एक ऐसा प्रशासनिक ढांचा तैयार करने का है जो हवा के इस भारी और वास्तविक संकट का दृढ़ता से मुकाबला कर सके।

लेखक पंजाब विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं।

अटलांटिक के ठंडे पानी से मॉनसून में बदलाव

मुकुल व्यास

एक नई रिसर्च से पता चलता है कि उत्तरी अटलांटिक महासागर में पानी के एक ठंडे हिस्से ने जेट स्ट्रीम हवाओं के जरिए भारतीय गर्मियों के मॉनसून में बदलाव शुरू कर दिए हैं। इससे करोड़ों लोगों की रोजी-रोटी को खतरा पैदा हो गया है।

मॉनसून हमारी जीवन रेखा है। भारत और दक्षिण एशिया के दूसरे हिस्सों में 1 अरब से अधिक लोग खाद्य सुरक्षा और आर्थिक स्थिरता के लिए मॉनसून पर निर्भर हैं। हर साल हम एक अच्छे मॉनसून की प्रतीक्षा करते हैं। लेकिन वैज्ञानिकों ने पाया है कि पिछले कुछ वर्षों से भारतीय मॉनसून के पैटर्न में परिवर्तन हो रहा है। वैज्ञानिक इस बदलाव के कारणों को जानने की कोशिश कर रहे हैं। अब एक नई रिसर्च से पता चलता है कि उत्तरी अटलांटिक महासागर में पानी के एक ठंडे हिस्से ने जेट स्ट्रीम हवाओं के जरिए भारतीय गर्मियों के मॉनसून में बदलाव शुरू कर दिए हैं। इससे करोड़ों लोगों की रोजी-रोटी को खतरा पैदा हो गया है। वैज्ञानिकों का कहना है कि इन दोनों प्रणालियों के बीच का संबंध एक ऐसे पहले से अज्ञात संबंध को दिखाता है जो दक्षिण एशिया में मौसम के अनुमानों को जानकारी दे सकता है और दूसरी जगहों पर मौसम की घटनाओं पर रोशनी डाल सकता है।

ध्यान रहे कि जेट स्ट्रीम हवाएं पृथ्वी के वायुमंडल में 9 से 16 किलोमीटर की ऊंचाई पर बहने वाली तेज गति वाली, संकरी वायुधाराएं हैं। तापमान के अंतर और पृथ्वी के घूर्णन से संचालित ये हवाएं वायुमंडलीय सीमाओं के रूप में कार्य करती हैं जो वैश्विक मौसम के पैटर्न को आकार देती हैं और वाणिज्यिक विमानन मार्गों को प्रभावित करती हैं।

भारतीय गर्मियों का मॉनसून वर्षा का एक पैटर्न है जो जून से सितंबर तक रहता है और यह गर्म उत्तरी हिंद महासागर और भूमध्य रेखा के नीचे ठंडे समुद्री पानी के बीच तापमान के अंतर से चलता है। शुरू में, मॉनसून ने भारत के पश्चिमी तट और उत्तरी भारत के एक बड़े इलाके (गंगा के मैदान) में भारी बारिश शुरू की थी। लेकिन 1999 से यह पैटर्न बहुत बदल गया है। शोधकर्ताओं ने एक नए अध्ययन में पाया कि उत्तर-पश्चिम भारत में अब मॉनसून सीजन में 1999 से पहले के मुकाबले लगभग 25 प्रतिशत ज्यादा बारिश होती है, जबकि गंगा के मैदानी इलाकों में लगभग 4 प्रतिशत कम बारिश होती है।

इस अध्ययन के पहले लेखक और भारतीय विज्ञान संस्थान के जलवायु वैज्ञानिक महेंद्र निम्माकांति ने कहा कि यह परिवर्तन किसानों के लिए खास तौर पर बहुत बुरा है, क्योंकि उनके खेतों की मिट्टी और फसलें बारिश के पुराने पैटर्न के हिसाब से ढल गई हैं। उन्होंने कहा कि भारत काफी हद तक खेती पर निर्भर है। उत्तर-पश्चिम भारत में सामान्य से अधिक बारिश होने पर अचानक बाढ़ आ जाती है और फसलों का नुकसान होता है, क्योंकि इस इलाके की खेती सूखे हालात के हिसाब से ढल गई है।

इस बीच, गंगा के मैदानी इलाकों में सूखे के दौर भी आए हैं, जिससे फसलों में भी कमी आई है और किसानों की रोजी-रोटी पर असर पड़ा है।

पिछले अध्ययनों ने भारतीय मॉनसून में परिवर्तन को अटलांटिक मेरिडियनल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन (एएमओसी) में बदलाव से जोड़ा था। एएमओसी अटलांटिक में समुद्री धाराओं का एक बड़ा जाल है जो वैश्विक जलवायु को नियमित करता है और उत्तरी गोलार्द्ध में गर्मी पहुंचाता है। आंकड़े बताते है कि जलवायु परिवर्तन की वजह से एएमओसी धीमा हो रहा है और उत्तरी अटलांटिक महासागर में पहले के मुकाबले कम गर्मी छोड़ रहा है। निम्माकांति ने कहा कि इन अध्ययनों में यह नहीं बताया गया कि भारतीय मॉनसून कैसे बदल सकता है। इसके पीछे के तंत्र को भी विस्तार से नहीं समझाया गया। उन्होंने कहा, ये अध्ययन आम तौर पर यह समझाते हैं कि अगर एएमओसी कमजोर होता है, तो यह भारतीय मॉनसून को भी कमजोर करता है।

एक बड़ी समस्या यह है कि मौजूदा जलवायु मॉडल भारतीय मॉनसून में हुए बदलावों को नहीं दिखाते हैं, क्योंकि वे उत्तरी अटलांटिक महासागर की सतह के तापमान में बदलाव को भी पूरी तरह से ग्रहण नहीं करते हैं। इन मॉडलों ने ग्रीनलैंड के दक्षिण-पूर्व में एक अत्यंत ठंडे क्षेत्र पर गौर नहीं किया जिसे 'कोल्ड ब्लॉब' के नाम से जाना जाता है, जहां 1901 और 2021 के बीच पानी 1800 के दशक के आखिर की तुलना में ज्यादा ठंडा था। कोल्ड ब्लॉब बताता है कि एएमओसी कमजोर हो रहा है क्योंकि यह उत्तरी अटलांटिक तक पहुंचने वाली गर्मी की मात्रा में कमी की ओर इशारा करता है।

यह पता लगाने के लिए कि भारतीय मानसून कैसे और क्यों बदला है, शोधकर्ताओं ने दर्जनों जलवायु मॉडलों में बारिश का डेटा, समुद्र की सतह के तापमान के रिकॉर्ड और असल जिंदगी के दूसरे अवलोकन डाले। इसने पिछले 27 सालों में देखे गए बदलावों को फिर से दिखाया। इन नतीजों से उत्तरी अटलांटिक में हुए बदलावों और मानसून में बदलावों के बीच संबंध का पता चला। यह जानने के लिए क्या उत्तरी अटलांटिक समुद्र की सतह के तापमान की वजह से भारतीय मानसून अजीब तरह से बर्ताव कर रहा है, टीम ने एक सिमुलेशन (कंप्यूटर पर परिस्थितियों की नक़ल) में कोल्ड ब्लॉब को जोड़ा और हटाया।

नतीजों से पता चला कि ठंडे ब्लॉब ने उत्तरी अटलांटिक पर एक मजबूत टेम्परेचर ग्रेडिएंट (तापमान में परिवर्तन की दर और दिशा का पैमाना) बनाकर भारतीय मानसून को शिफ्ट कर दिया है, जो बदले में यूरेशिया के ऊपर वायुमंडल में जेट स्ट्रीम हवाओं और प्रेशर सिस्टम पर असर डालता है। खासकर, उत्तरी अटलांटिक के ऊपर जेट स्ट्रीम तेज हो गई है, और पश्चिमी रूस में यूराल पहाड़ों के ऊपर एक 'ब्लॉकिंग' सिस्टम मजबूत हो गया है। इसके परिणामस्वरूप भारत में मौसम सिस्टम बदल गए हैं, जो नमी वाली हवा को देश के उत्तर-पश्चिम की ओर ले जा रहे हैं और उसे दूसरे इलाकों से दूर खींच रहे हैं।

एजीयू एडवांसेज जर्नल में छपे नए नतीजों से मौसम का अनुमान लगाने वालों को भारत और पड़ोसी देशों में मॉनसून के दौरान बहुत ज्यादा बारिश और सूखे जैसी घटनाओं का अनुमान लगाने में मदद मिल सकती है। कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि भारतीय मॉनसून वैश्विक जलवायु में एक निर्णायक बिंदु (टिपिंग प्वाइंट) है, और इन निष्कर्षों से पता चलता है कि यह सिस्टम 1999 में एक अहम सीमा पार कर गया था। तब से कोल्ड ब्लॉब की वजह से जेट स्ट्रीम में लगातार बदलाव हुआ है, जिससे मॉनसून में अचानक बदलाव आए हैं। अभी यह साफ नहीं है कि तेजी से बदलती जलवायु में भारतीय मॉनसून कैसे बदलेगा, क्योंकि जलवायु मॉडल उत्तर अटलांटिक के बारे में अलग-अलग अनुमान लगाते हैं, और दुनिया के बदलने के साथ-साथ दूसरे कारण भी असर डाल सकते हैं।

लेखक विज्ञान मामलों के जानकार हैं।

ITR फाइल 500/-
Whatsapp पर बनवाएँ
Income Tax फाइल, GST रजिस्ट्रेशन, TDS रिफंड, प्रोजेक्ट रिपोर्ट
CMA DATA, MSME, BALANCE SHEET, फूड लाइसेंस
हमारे Tax Expert आपकी मदद हेतु तैयार है।
सम्पर्क - शेखर गुप्ता 9300755544 - 8878655544
www.onlytds.com

श्रीकंचनपथ
भिलाई-दुर्ग

प्रिंट और डीजिटल मीडिया में
सभी प्रकार के विज्ञापन
के लिए
संपर्क करे
Mob.-:
9303289950
7987166110

प्रमुख खबरें

आधार नामांकन एवं अपडेट कार्यों की गुणवत्ता बढ़ाने जिला स्तरीय प्रशिक्षण आयोजित

दुर्ग। कलेक्टर अभिजीत सिंह के निर्देशन में लोक निर्माण विभाग के मीटिंग हॉल में जिला दुर्ग के आधार ऑपरेटरों के लिए एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रशिक्षण में दुर्ग जिले के 58 तथा खैरागढ़ जिले के 4 आधार ऑपरेटरों ने भाग लिया। प्रशिक्षण भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के असिस्टेंट मैनेजर मो. सौबान मोहिदीन द्वारा प्रदान किया गया। प्रशिक्षण का उद्देश्य आधार नामांकन एवं आधार अद्यतन कार्यों को यूआईडीएआई के नवीनतम दिशा-निर्देशों के अनुरूप अधिक गुणवत्तापूर्ण, पारदर्शी एवं त्रुटिरहित बनाना था। प्रशिक्षण के दौरान ऑपरेटरों को दस्तावेज़ सत्यापन, तकनीकी अपडेट, जन्मतिथि संशोधन, जेंडर लिमिट क्रॉस, नाम लिमिट क्रॉस, पेनल्टी संबंधी प्रावधान, आधार रद्द एवं निष्क्रिय मामलों के संबंध में विस्तृत जानकारी दी गई। साथ ही ऑपरेटरों द्वारा उठाए गए विभिन्न तकनीकी एवं कार्य संबंधी प्रश्नों का विस्तार से समाधान किया गया। कार्यक्रम में ई-डिस्ट्रिक्ट प्रबंधक, जिला समन्वयक एवं एमटीओ भी उपस्थित रहे। प्रशिक्षण के माध्यम से आधार सेवाओं को और अधिक प्रभावी, सटीक एवं नागरिकों के लिए सुविधाजनक बनाने पर विशेष जोर दिया गया।

जिले में 11 से 18 जुलाई तक मनाया जाएगा जनसंख्या स्थिरीकरण पखवाड़ा

दुर्ग। जिले में कलेक्टर अभिजीत सिंह के मार्गदर्शन में तथा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के नेतृत्व में आगामी 11 से 18 जुलाई 2026 तक जनसंख्या स्थिरीकरण पखवाड़े का विशेष आयोजन किया जा रहा है। ''जब बच्चों में हो सही अंतराल, परिवार बने स्वस्थ और खुशहाल'' ध्येय के साथ मनाए जाने वाले इस अभियान का मुख्य उद्देश्य समुदाय को गर्भधारण के उचित समय, दो बच्चों के मध्य न्यूनतम 3 साल का सुरक्षित अंतराल रखने और परिवार नियोजन के प्रति जागरूक करना है, जिससे मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य में गुणात्मक सुधार लाया जा सके। अभियान के दौरान आम जनता के बीच व्याप्त भ्रांतियों को दूर करने और परिवार नियोजन सेवाओं की उपयोगिता बताने के लिए सभी विकासखंडों के सामुदायिक व प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों तथा आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में 'सास-बहू सम्मेलन' एवं 'मोर मितान मोर संगवारी चौपाल' जैसे जागरूक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। इस पखवाड़े की सफलता के लिए वर्तमान में स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं द्वारा लक्षित दंपत्तियों से घर-घर संपर्क कर स्वास्थ्य सेवाओं का परामर्श दिया जा रहा है। जिला परिवार कल्याण कार्यक्रम नोडल अधिकारी डॉ. अर्चना चौहान ने बताया कि जिला चिकित्सालय सहित समस्त स्वास्थ्य केंद्रों में परिवार नियोजन के स्थायी और अस्थायी साधन पूरी तरह निःशुल्क उपलब्ध हैं। सरकार द्वारा परिवार नियोजन अपनाने वाले लाभार्थियों को आर्थिक प्रोत्साहन राशि भी दी जाती है, जिसके तहत महिला नसबंदी के लिए 2,000/- रुपये तथा पुरुष नसबंदी के लिए 3,000/- रुपये की राशि प्रदान की जाती है।

एमएसएमई आइडिया हैकथॉन 6.0 व फ्रंटियर टेक्नोलॉजी पर चेम्बर और रूंगटा कॉलेज के बीच चर्चा

श्रीकंचनपथ न्यूज

भिलाई। बुधवार को छत्तीसगढ़ चेम्बर ऑफकॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, भिलाई इकाई एवं रूंगटा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के मध्य उद्योग, नवाचार एवं तकनीकी विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई।

बैठक में एमएसएमई आइडिया हैकथॉन 6.0 तथा फ्रंटियर टेक्नोलॉजी जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तृत एवं सार्थक चर्चा हुई। इस दौरान नवाचार आधारित उद्यमिता, स्टार्टअप संस्कृति, तकनीकी अनुसंधान तथा उद्योगों की वास्तविक समस्याओं के समाधान हेतु विद्यार्थियों एवं युवा नवप्रवर्तकों की सहभागिता बढ़ाने पर विशेष जोर दिया गया। बैठक में यह विचार रखा गया कि उद्योग जगत चेम्बर के साथ व रूंगटा कालेज के बीच समन्वय स्थापित कर युवाओं के नवाचारों को व्यावसायिक अवसरों से जोड़ा जाए, जिससे नए स्टार्टअप विकसित हों तथा एमएसएमई क्षेत्र को नई तकनीकों का लाभ मिल सके।

दोनों संस्थानों ने भविष्य में संयुक्त रूप से कार्यशालाओं, सेमिनारों, हैकथॉन एवं नवाचार आधारित कार्यक्रमों के आयोजन की दिशा में सहयोग करने पर सहमति व्यक्त की।

महामंत्री आइस पहल से क्षेत्र के युवाओं, उद्योगों एवं स्टार्टअप इकोसिस्टम को नई दिशा मिलने की उम्मीद जताई गई।

इस महत्वपूर्ण बैठक में महामंत्री अजय भसीन,भिलाई चेम्बर अध्यक्ष गार्गी शंकर मिश्रा,महिला चेम्बर प्रभारी सरोजनी पाणिग्रही, अमन मिश्रा,शंकर सचदेव,सुनील मिश्र,निरंकार सिंह व रूंगटा कालेज से जी.वेणुगोपाल जी एवम अनुराग शर्मा जी उपस्थित थे।

विधायक रिकेश सेन की पहल : भाजपा कार्यकर्ताओं के लिए 8 कल्याणकारी योजनाओं का शुभारंभ

श्रीकंचनपथ न्यूज

भिलाई। वैशाली नगर विधानसभा क्षेत्र के विधायक रिकेश सेन ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और उनके परिवारों के सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक एवं स्वास्थ्य सुरक्षा को मजबूत करने के उद्देश्य से 8 विशेष कल्याणकारी योजनाओं की घोषणा की है। इन योजनाओं का उद्देश्य पार्टी के समर्पित कार्यकर्ताओं और उनके परिवारों को जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग एवं सुरक्षा प्रदान करना है। विधायक रिकेश सेन ने कहा कि भाजपा कार्यकर्ता संगठन की रीढ़ हैं। प्रत्येक कार्यकर्ता समाज और राष्ट्रहित में निस्वार्थ भाव से कार्य करता है। ऐसे समर्पित कार्यकर्ताओं और उनके परिवारों की सुरक्षा एवं सम्मान सुनिश्चित करना हम सभी की जिम्मेदारी है। इन्हीं भावनाओं को ध्यान में रखते हुए इन योजनाओं की शुरुआत की गई है। विधायक रिकेश सेन ने कहा कि इन योजनाओं का उद्देश्य कार्यकर्ताओं को केवल सम्मान देना ही नहीं, बल्कि उनके परिवारों को सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य और आर्थिक संबल उपलब्ध कराना भी है। यह पहल कार्यकर्ताओं के मनोबल को और अधिक मजबूत करेगी तथा संगठन और समाज सेवा के प्रति उनका समर्पण और बढ़ेगा।

योजनाओं का विवरण

- कमल परिवार सुरक्षा योजना-भाजपा कार्यकर्ताओं के परिवारों को 5 लाख तक कैशलेस उपचार एवं 10 लाख का दुर्घटना बीमा उपलब्ध कराया जाएगा।
- कमल विद्या निधि योजना-कार्यकर्ताओं के मेधावी बच्चों को प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। 10वीं में 90% या अधिक अंक पर 5,000, 12वीं में 90% या अधिक अंक पर 10,000 रूपये। NEET, JEE एवं अन्य प्रोफेशनल कोर्स में प्रवेश पर 25,000 रूपये।
- कमल रोजगार सहायता योजना-रोजगार एवं स्व रोजगार को बढ़ावा देने के लिए 50,000 तक ब्याजमुक्त ऋण तथा निःशुल्क प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जाएगा।
- कमल गृह आवास सहायता योजना-घर की मरम्मत, शौचालय निर्माण एवं सोलर सुविधा के लिए 25,000 तक की सहायता प्रदान की जाएगी।
- कमल पेंशन योजना-65 वर्ष से अधिक आयु के आर्थिक रूप से कमजोर भाजपा कार्यकर्ताओं को 2,000 प्रतिमाह पेंशन दी जाएगी।
- कमल धार्मिक तीर्थ यात्रा योजना-भाजपा कार्यकर्ताओं को वर्ष में एक बार परिवार सहित छत्तीसगढ़ के किसी भी तीर्थस्थल की यात्रा की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।
- कमल स्वास्थ्य योजना-कार्यकर्ताओं एवं उनके परिवार के सभी सदस्यों को सीटी स्कैन, एमआरआई, सोनोग्राफी, एक्स-रे, अल्ट्रासाउंड एवं एंडोस्कोपी जैसी जांचें निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएंगी।
- कमल आर्थिक सहायता योजना-भाजपा कार्यकर्ता के परिवार में मृत्यु होने पर दशगात्र संस्कार हेतु 20,000 की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।

66 सरकारी स्कूलों के कक्ष किए जाएंगे डिस्मेंटल

दुर्ग। जिले में स्कूली बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन द्वारा एक बड़ा कदम उठाया गया है। कलेक्टर अभिजीत सिंह ने जिले के विभिन्न शासकीय विद्यालयों के जर्जर हो चुके भवनों और कमरों को डिस्मेंटल (ध्वस्त) करने की अनुमति दे दी है । जिला शिक्षा अधिकारी और लोक निर्माण विभाग दुर्ग संभाग के प्रतिवेदन और प्रस्ताव के आधार पर इन अनुपयोगी और असुरक्षित ढांचों को निष्प्रयोज्य घोषित किया गया है। कलेक्टर द्वारा जारी निर्देश में स्पष्ट किया गया है कि वर्तमान में चिन्हित किए गए स्कूलों के अतिरिक्त, क्षेत्र के अन्य जर्जर भवनों (शेष) का भी लोक निर्माण विभाग द्वारा लगातार निरीक्षण कर प्रतिवेदन तैयार किया जा रहा है, जिसके आधार पर शीघ्र ही उन्हें भी डिस्मेंटल करने की अनुमति प्रदान की जाएगी। जिले के तीनों प्रमुख विकासखंडों के कुल 66 शासकीय स्कूलों में यह कार्रवाई की जाएगी।

कलेक्टर ने किया अन्नपूर्ति ग्रीन एटीएम का निरीक्षण

श्रीकंचनपथ न्यूज

दुर्ग। जिले का पहला अन्नपूर्ति ग्रीन एटीएम सुपेला के गदा चौक स्थित अम्बेडकर नगर में शुरू होने जा रहा है। इस अत्याधुनिक व्यवस्था के माध्यम से राशनकार्डधारी अब 24 घंटे अपनी सुविधा अनुसार चावल प्राप्त कर सकेंगे। कलेक्टर अभिजीत सिंह ने अन्नपूर्ति ग्रीन एटीएम का निरीक्षण कर शुभारंभ की तैयारियों का जायजा लिया तथा सुरक्षा एवं संचालन के लिए चौकीदार और ऑपरेटर की दो शिफ्ट में ड्यूटी लगाने के निर्देश दिए।

वन नेशन, वन राशनकार्ड योजना के तहत राशनकार्डधारी, चाहे वह जिले के किसी भी क्षेत्र में निवास करता हो या किसी भी उचित मूल्य दुकान से राशन प्राप्त करता हो, अम्बेडकर नगर स्थित इस ग्रीन एटीएम से अपने हिस्से का चावल प्राप्त कर सकेगा। अन्नपूर्ति ग्रीन एटीएम का संचालन महिला स्व-सहायता समूह द्वारा किया जाएगा। समूह की सदस्य मशीन में चावल की आपूर्ति, संचालन एवं हितग्राहियों की सहायता के लिए उपस्थित रहेंगी। वहीं इच्छुक हितग्राही स्वयं भी मशीन का उपयोग कर चावल प्राप्त कर सकेंगे। एटीएम की क्षमता 2.7 मीट्रिक टन है। इस व्यवस्था से लोगों को उचित मूल्य की दुकानों पर लंबी कतारों में खड़े रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी और राशन वितरण प्रक्रिया अधिक पारदर्शी, तेज एवं सुविधाजनक बनेगी।

ऐसे करेगा काम अन्नपूर्ति ग्रीन एटीएम

मशीन से चावल प्राप्त करने के लिए हितग्राही को सबसे पहले अपना राशनकार्ड नंबर दर्ज करना होगा। इसके बाद बायोमेट्रिक सत्यापन (अंगूठे का निशान) करना होगा। सत्यापन पूर्ण होते ही पात्रता के अनुसार निर्धारित मात्रा में चावल मशीन से स्वतः उपलब्ध हो जाएगा। केवल शासन द्वारा जारी वैध राशनकार्डधारियों को ही इस सुविधा का लाभ मिलेगा। इस दौरान खाद्य नियंत्रक अनुराग भदौरिया सहित विभाग के अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित थे।

आईआईटी भिलाई और 506 आर्मी बेस वर्कशॉप जबलपुर के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर

श्रीकंचनपथ न्यूज

भिलाई। राष्ट्रीय महत्व के संस्थान, आईआईटी भिलाई और भारतीय सेना के तहत रखरखाव और तकनीकी सहायता देने वाले प्रमुख संस्थान, 506 आर्मी बेस वर्कशॉप ने 8 जुलाई 2026 को आईआईटी भिलाई कैंपस में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। यह समझौता ज्ञापन आईआईटी भिलाई के निदेशक प्रो. राजीव प्रकाश और 506 आर्मी बेस वर्कशॉप के कमांडेंट और मैनेजिंग डायरेक्टर ब्रिगेडियर टी. ए. अरविंद की मौजूदगी में किया गया।

इस एमओयू का मकसद आपसी सहमति वाले क्षेत्रों में फैकल्टी सदस्यों, तकनीकी कर्मचारियों और रिसर्च स्कॉलर्स के ज़रिए एकेडमिक और तकनीकी जानकारी उपलब्ध कराना है।

वे संयुक्त रिसर्च और डेवलपमेंट गतिविधियां करेंगे, जिनमें उभरती हुई टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, डिज़ाइन, एनालिसिस, मैन्युफैक्चरिंग, टेस्टिंग, रिलायबिलिटी, मटीरियल्स, सरफेस इंजीनियरिंग, रोबोटिक्स, ऑटोमेशन, AI/ML-आधारित इंजीनियरिंग समाधान, सेंसर, एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग, मरम्मत और री-मैन्युफैक्चरिंग और अन्य संबंधित क्षेत्र शामिल हैं।

सहयोग के कुछ संभावित क्षेत्रों में उभरती हुई और रक्षा-संबंधी टेक्नोलॉजी में संयुक्त रिसर्च और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट शामिल हैं। इसके अलावा तकनीकी वर्कशॉप, सेमिनार, एक्सपर्ट लेक्चर और क्षमता-निर्माण कार्यक्रम; छात्रों के लिए इंटर्नशिप, प्रोजेक्ट वर्क और रिसर्च का अनुभव पाने के मौके; सेना के तकनीकी संस्थानों के साथ फैकल्टी का तालमेल; और अधिकारियों व तकनीकी कर्मचारियों के लिए कौशल विकास और विशेष ट्रेनिंग कार्यक्रम आदि भी शामिल हैं। यह एमओयू बड़े पैमाने पर संस्थागत कामकाज को मज़बूत करेगा।

सड़क चौड़ीकरण से प्रभावित ग्रामीणों ने मुआवजा दिलाने जनदर्शन में दिया आवेदन

पानी निकासी बंद होने से खेतों में जलभराव, किसानों ने कलेक्टर से लगाई गुहार

श्रीकंचनपथ न्यूज

दुर्ग। जिला कार्यालय के सभाकक्ष में कलेक्टर अभिजीत सिंह ने जनदर्शन कार्यक्रम में पहुंचे जनसामान्य लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी। उन्होंने जनदर्शन में पहुंचे सभी लोगों की समस्याओं को गंभीरता से सुना और समुचित समाधान एवं निराकरण करने संबंधित विभागों को शीघ्र कार्यवाही कर आवश्यक पहल करने को कहा। जनदर्शन में अपर कलेक्टर वीरेन्द्र सिंह भी उपस्थित थे। जनदर्शन में अवैध कब्जा, आवासीय पट्टा, प्रधानमंत्री आवास, भूमि सीमांकन कराने, सीसी रोड निर्माण, ऋण पुस्तिका सुधार, आर्थिक सहायता राशि दिलाने सहित विभिन्न मांगों एवं समस्याओं से संबंधित आज 127 आवेदन प्राप्त हुए। जनदर्शन में प्राप्त विभिन्न आवेदनों पर कलेक्टर ने तत्काल संज्ञान लेते हुए संबंधित अधिकारियों से फोन पर जानकारी ली और उक्त आवेदनों पर आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए।

इसी कड़ी में ग्राम अंजोरा के किसानों ने खेतों में बरसाती पानी की निकासी कराने की मांग की है।

किसानों ने बताया कि गांव के एक किसान द्वारा अपने खेत में ऊंची मेड़ बना देने से बरसाती पानी का प्राकृतिक बहाव रुक गया है। वर्षों से खेतों का बरसाती पानी एक-दूसरे के खेतों से होकर निकलता रहा है, लेकिन पानी की निकासी बंद होने से कई किसानों के खेतों में जलभराव हो गया है। इससे धान की फसल के खराब होने की आशंका बढ़ गई है और किसानों को लाखों रुपये के नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। इस पर कलेक्टर ने जनपद दुर्ग सीईओ को निरीक्षण कर आवश्यक कार्यवाही करने को कहा। ग्राम परसाही के ग्रामीणों ने सड़क चौड़ीकरण से प्रभावित परिवारों को शीघ्र मुआवजा दिलाने की मांग की। ग्रामीणों ने बताया कि परसाही से सिरी मार्ग के चौड़ीकरण के दौरान करीब 50 परिवारों के मकान प्रभावित हुए थे, जिनमें कई मकान गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हुए। ग्रामीणों ने बताया कि जनवरी 2024 में मकान टूटने के बाद से अब तक किसी भी प्रभावित परिवार को मुआवजा नहीं मिला है। इस संबंध में संबंधित विभाग को भी आवेदन दिए जा चुके हैं।

ग्रामीणों ने कलेक्टर से प्रभावित परिवारों को जल्द मुआवजा राशि दिलाने की मांग की है। इस पर कलेक्टर ने एसडीएम पाटन को नियमानुसार कार्यवाही करने को कहा। उल्लास नगर, बॉम्बे आवास और अयप्पा नगर के रहवासियों ने जाम नालियों, जलभराव और दूषित पेयजल की समस्या के संबंध में आवेदन दिया। रहवासियों ने बताया कि अवैध अतिक्रमण हटाए जाने के बाद नाली पूरी तरह जाम हो गई है, जिससे गंदा पानी घरों के सामने और आसपास जमा हो रहा है।

गंदे पानी के बीच से पेयजल पाइपलाइन गुजरने के कारण पानी दूषित होने की आशंका है। साथ ही क्षेत्र में दुर्गंध, मच्छरों का प्रकोप बढ़ने से डेंगू, मलेरिया और अन्य संक्रामक बीमारियों का खतरा भी मंडरा रहा है। इस संबंध में वार्ड पार्षद और नगर निगम में इसकी शिकायत की गई थी। इस पर कलेक्टर ने नगर निगम भिलाई आयुक्त को निरीक्षण कर आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए।

Since 1972
CROWN-TV
Choice Of Millions
LED / Washing Machine
Cooler / Fridge
Available All Size
CONTACT :
Atlas Radio Traders (Crown)
Sect.-3, D-48, Ward No. 13
Devendra Nagar, Raipur (C.G.) 492009
Near Akash Gas Agency Line
Mob.: 98262 52372

खास-खबर

हाईकोर्ट का फैसलाः दृष्टिबाधित पीटीआई शिक्षकों की नौकरी नहीं छीन सकती सरकार

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने दिव्यांग कर्मचारियों के अधिकारों से जुड़े एक महत्वपूर्ण मामले में फैसला सुनाते हुए कहा है कि यदि भर्ती विज्ञापन में किसी विशेष दिव्यांगता को अयोग्य घोषित नहीं किया गया है, तो चयन प्रक्रिया पूरी होने और नियुक्ति के बाद सरकार किसी प्रशासनिक समिति की रिपोर्ट के आधार पर कर्मचारी की सेवा समाप्त नहीं कर सकती। हाईकोर्ट ने इस तरह की कार्रवाई को मनमाना बताते हुए दो दृष्टिबाधित शिक्षकों के पक्ष में फैसला सुनाया है। जस्टिस एन.के. चंद्रवंशी- की एकलपीठ ने शिक्षक पद पर नियुक्त दृष्टिबाधित शिक्षक -शिव शंकर साहू- और -नील कुमारी- की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए शिक्षा विभाग द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस और बर्खास्तगी आदेश को निरस्त कर दिया।

13 युवाओं को मिला ऑफर लेटर

रायपुर। नौकरी की तलाश में पहुंचे युवाओं के लिए बुधवार का दिन खुशखबरी लेकर आया। बलौदाबाजार जिला रोजगार कार्यालय परिसर में आयोजित रोजगार मेले में 13 युवाओं को मौके पर ही ऑफर लेटर सौंपे गए, जबकि 43 अभ्यर्थियों का विभिन्न निजी कंपनियों में प्राथमिक चयन हुआ। युवाओं में रोजगार को लेकर नई उम्मीद जगी। कलेक्टर के मार्गदर्शन में आयोजित रोजगार मेले में निजी क्षेत्र की पांच कंपनियों ने 234 पदों पर भर्ती के लिए हिस्सा लिया। मेले के लिए 476 युवाओं ने ऑनलाइन आवेदन किया था, जिनमें से 147 अभ्यर्थी साक्षात्कार में शामिल हुए। मेले में ऋषभ वेंचर्स ने सबसे अधिक 9 युवाओं को ऑन द स्पॉट ऑफर लेटर दिए, जबकि यूनिक्स सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड ने 4 अभ्यर्थियों को तत्काल नियुक्ति पत्र सौंपे। भारतीय जीवन बीमा, किरण एग्रीकल्चर और आश्रव फाउंडेशन एंड सिक्योरिटी सहित अन्य संस्थानों ने भी विभिन्न पदों के लिए अभ्यर्थियों का चयन किया।

जोगी कांग्रेस 2.0 की शुरुआत, युवा नेतृत्व के साथ किया बड़ा ऐलान

रायपुर। छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस (जे) ने नए स्वरूप और नई रणनीति के साथ अपनी राजनीतिक पारी शुरू करने का ऐलान किया है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष -अमित जोगी- ने रायपुर स्थित अपने निवास पर आयोजित पत्रकार वार्ता में जोगी कांग्रेस 2.0- लॉन्च करते हुए पार्टी का नया विजन और भविष्य की रणनीति प्रस्तुत की। अमित जोगी ने कहा कि वर्तमान समय की राजनीति पारंपरिक सोच से आगे बढ़ चुकी है और अब नई तकनीक, नई सोच तथा युवा नेतृत्व के साथ आगे बढ़ने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि पार्टी अब वंशवाद, जाति और धर्म की राजनीति से ऊपर उठकर जनता के जमीनी मुद्दों पर काम करेगी। इस अवसर पर पार्टी के युवा संगठन में बड़ा बदलाव करते हुए -अजीत जोगी युवा कांग्रेस- का नाम बदलकर -जनता युवा कांग्रेस- कर दिया गया। पार्टी संस्थापक -अजीत जोगी- के नाम को युवा विंग से हटाने का निर्णय लिया गया। जनता युवा कांग्रेस की कमान -ईश्वर उपाध्याय- को सौंपी गई है, जो अब युवा संगठन का नेतृत्व करेंगे। अमित जोगी ने घोषणा की कि पार्टी प्रदेशभर में -नशा, बेरोजगारी और अन्याय- के खिलाफ व्यापक जन अभियान चलाएगी। उन्होंने कहा कि जनता युवा कांग्रेस बेटी बचाओ के साथ-साथ -बेटा बचाओ अभियान भी शुरू करेगी। उनका कहना था कि प्रदेश के युवाओं को नशे, बेरोजगारी और अवसाद से बचाने की जरूरत है।

एसडीजी 2.0 और 'बस्तर अंजोर' से विकसित छत्तीसगढ़ के विजन को मिलेगी नई गति : मुख्यमंत्री

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने मंत्रालय महानदी भवन में मंत्रिपरिषद के सदस्यों की उपस्थिति में राज्य नीति आयोग द्वारा तैयार छत्तीसगढ़ एस.डी.जी. 2.0 फ्रेमवर्क का विमोचन किया। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ एस.डी.जी. राज्य एवं जिला संकेतक फ्रेमवर्क 2.0 तथा मेटाडेटा हैंडबुक का भी विमोचन किया गया।

साथ ही बस्तर संभाग के समावेशी, अभिसरण आधारित और मापनीय विकास के लिए तैयार की गई अभिनव पहल 'बस्तर अंजोर' की भी शुरुआत की गई। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण के लिए योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन, सटीक डेटा और परिणाम आधारित मॉनिटरिंग अत्यंत आवश्यक है। एस.डी.जी. 2.0 फ्रेमवर्क शासन को साक्ष्य-आधारित नीति निर्माण, बेहतर अंतर-विभागीय समन्वय तथा योजनाओं की नियमित निगरानी के लिए एक सशक्त आधार प्रदान करेगा। उन्होंने कहा कि यह पहल 'विकसित छत्तीसगढ़ @2047' के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार का उद्देश्य केवल विकास योजनाएं संचालित करना नहीं, बल्कि उनके वास्तविक प्रभाव को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना है। एस.डी.जी. 2.0 के माध्यम से विकास की प्रगति को अधिक पारदर्शी, मापनीय और जवाबदेह बनाया जा सकेगा। नए एस.डी.जी. 2.0 फ्रेमवर्क के अंतर्गत राज्य स्तर पर संकेतकों की संख्या 275 से बढ़ाकर 343 तथा जिला स्तर पर 82 से बढ़ाकर 99 कर दी गई है। इससे विकास कार्यों की अधिक व्यापक, सटीक और वैज्ञानिक निगरानी संभव होगी। मेटाडेटा हैंडबुक में प्रत्येक संकेतक की गणना पद्धति एवं रिपोर्टिंग प्रणाली को मानकीकृत किया गया है, जिससे पूरे राज्य में डेटा की गुणवत्ता और विश्वसनीयता सुनिश्चित होगी।

इस अवसर पर राज्य नीति आयोग के उपाध्यक्ष गणेश शंकर मिश्रा ने 'बस्तर अंजोर' की अवधारणा प्रस्तुत करते हुए बताया कि यह अभिसरण (कन्वर्जेंस) आधारित विकास मॉडल है, जिसे बस्तर संभाग को देश का सर्वाधिक विकसित जनजातीय क्षेत्र बनाने के संकल्प को मूर्त रूप देने के उद्देश्य से तैयार किया गया है। उन्होंने बताया कि 'बस्तर अंजोर' के 3+4 मॉडल के अंतर्गत जिला स्तर की तीन प्रमुख पहल - नियद नेल्लानार 2.0, बस्तर मुन्ने और स्वस्थ बस्तर - का अभिसरण चार प्रमुख राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय विकास फ्रेमवर्क - एस.डी.जी. 2030, विकसित छत्तीसगढ़ ञ2047, आकांक्षी जिला एवं विकासखंड कार्यक्रम से किया गया है। इसका उद्देश्य अतिरिक्त संसाधनों के बिना बेहतर समन्वय के माध्यम से शिक्षा, स्वास्थ्य, आजीविका और अधोसंरचना जैसे क्षेत्रों में ठोस एवं मापनीय परिणाम प्राप्त करना है।

'बस्तर अंजोर' अंत्योदय से सर्वोदय की भावना पर आधारित एक दूरदर्शी पहल है, जो बस्तर को समावेशी, सतत एवं परिणामोन्मुख विकास का राष्ट्रीय मॉडल बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री अरुण साव, उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा, मंत्रिपरिषद के सदस्य, मुख्य सचिव विकास शील, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव सुबोध कुमार सिंह तथा वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित थे।

कर्मचारियों की गरिमा और आर्थिक सुरक्षा के लिए मुख्यमंत्री साय की बड़ी पहल

शासकीय सेवकों के लिए वेतन के विरुद्ध अल्पावधि ऋण योजना का शुभारंभ

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर । मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने मंत्रालय महानदी भवन के सभागार में राज्य के शासकीय सेवकों के लिए वेतन के विरुद्ध अल्पावधि ऋ ण योजना का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने योजना के ब्रोशर का भी विमोचन किया। मुख्यमंत्री ने इसे कर्मचारी कल्याण, सुशासन और संवेदनशील प्रशासन की दिशा में राज्य सरकार की महत्वपूर्ण पहल बताते हुए कहा कि इसका उद्देश्य शासकीय सेवकों को आकस्मिक परिस्थितियों में सम्मानजनक, त्वरित और सहज वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना है।

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि शासकीय सेवक राज्य के विकास की रीढ़ हैं। जब कर्मचारी आर्थिक चिंताओं से मुक्त होकर कार्य करेंगे, तभी शासन की योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक प्रभावी ढंग से पहुंच सकेगा। उन्होंने कहा कि अब कर्मचारियों को आकस्मिक आवश्यकताओं के लिए निजी साहूकारों अथवा ऊंची ब्याज दरों पर ऋण लेने की विवशता का सामना नहीं करना पड़ेगा। सरकार ने उनकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए ऐसी व्यवस्था विकसित की है, जिसके माध्यम से वे बिना अनावश्यक कागजी प्रक्रिया के अपनी पात्रता के अनुसार अल्पावधि ऋण प्राप्त कर सकेंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि वित्त विभाग ने सूचना प्रौद्योगिकी का प्रभावी उपयोग करते हुए इस सुविधा को ई-कोष प्रणाली से एकीकृत किया है। यह व्यवस्था पूरी तरह डिजिटल, पेपरलेस, सुरक्षित और पारदर्शी है तथा इससे राज्य सरकार पर कोई अतिरिक्त वित्तीय भार भी नहीं आएगा। उन्होंने इस अभिनव पहल के लिए वित्त विभाग की टीम को बधाई देते हुए सभी शासकीय सेवकों से विकसित छत्तीसगढ़ और सुशासन के संकल्प को आगे बढ़ाने में सक्रिय भागीदारी निभाने का आह्वान किया।

वित्त मंत्री ओ.पी. चौधरी ने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार प्रशासनिक सुधारों और कर्मचारी हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। उन्होंने बताया कि कर्मचारियों के लिए कैशलेस मेडिकल सुविधा लागू करने के बाद अब वेतन के विरुद्ध अल्पावधि ऋण योजना प्रारंभ की गई है, जिससे तात्कालिक आवश्यकताओं के लिए बिना ब्याज वित्तीय सहायता उपलब्ध होगी। उन्होंने बताया कि पायलट चरण के मात्र दो माह में 73 हजार से अधिक कर्मचारियों ने पंजीयन कराया है तथा 27 हजार कर्मचारी इस सुविधा का लाभ प्राप्त कर चुके हैं। भविष्य में बेहतर क्रेडिट स्कोर वाले कर्मचारियों को प्रतिस्पर्धी ब्याज दरों पर अधिक राशि के ऋण की सुविधा उपलब्ध कराने की भी योजना है।

छत्तीसगढ़ कर्मचारी-अधिकारी संघ के प्रांतीय संयोजक कमल वर्मा ने मुख्यमंत्री के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह योजना कर्मचारियों की लंबे समय से महसूस की जा रही आवश्यकता को पूरा करेगी तथा आकस्मिक परिस्थितियों में उन्हें सम्मानजनक और त्वरित आर्थिक सहायता उपलब्ध कराएगी।

उल्लेखनीय है कि यह सुविधा ई-कोष प्रणाली से एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से संचालित होगी। कर्मचारी ई-कोष के एम्प्लॉयी कॉर्नर से ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। ई-केवाईसी, डिजिटल प्रमाणीकरण एवं सहमति की प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद ऋण स्वीकृति एवं वितरण त्वरित रूप से किया जाएगा। वित्त विभाग द्वारा जारी मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) के अनुसार पूरी व्यवस्था में डेटा सुरक्षा, गोपनीयता तथा डिजिटल प्रमाणीकरण के उच्च मानकों का पालन सुनिश्चित किया गया है।

प्रधानमंत्री आवास योजना से पूरा हुआ रामबती का सपना

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। प्रधानमंत्री आवास योजना भारत सरकार की एक प्रमुख कल्याणकारी योजना है, जिसका उद्देश्य बेघर लोगों और कच्चे मकानों में रहने वाले नागरिकों को बुनियादी सुविधाओं से युक्त पक्का घर उपलब्ध कराना है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के सशक्त नेतृत्व में प्रदेश में गरीब और जरूरतमंद परिवारों को पक्का आवास उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना का प्रभावी क्रियान्वयन किया जा रहा है।

इस योजना ने बीजापुर नगर पालिका क्षेत्र की निवासी रामबती के जीवन में भी नई खुशियां और सुरक्षा लेकर आई है। बीजापुर नगर पालिका के वार्ड क्रमांक 11 में रहने वाली रामबती पिछले लगभग 30 वर्षों से अपने परिवार के साथ रह रही हैं। पति के निधन के बाद परिवार की पूरी जिम्मेदारी उनके कंधों पर आ गई। होटल में काम कर उन्होंने अपने एक बेटे और दिव्यांग बेटी का पालन-पोषण किया। सीमित आय के कारण परिवार एक पुराने और जर्जर मकान में रहने को मजबूर था। बरसात के दिनों में छत से पानी टपकता था, जिससे उन्हें कई परेशानियों का सामना करना पड़ता था। रामबती का चयन प्रधानमंत्री आवास योजना के मोर जमीन, मोर मकान घटक के तहत किया गया। नगर पालिका बीजापुर और योजना से जुड़े अधिकारियों ने सर्वे कर उनका प्रस्ताव तैयार किया, जिसके बाद उन्हें पक्का आवास स्वीकृत हुआ। आर्थिक तंगी के कारण शुरुआत में रामबती मकान का निर्माण नहीं करा पा रही थीं। ऐसे समय में नगर पालिका बीजापुर और प्रधानमंत्री आवास योजना की टीम ने उन्हें लगातार मार्गदर्शन और तकनीकी सहयोग दिया। स्थानीय मिस्त्री की मदद से उन्होंने धीरे-धीरे अपने सपनों का पक्का घर तैयार कर लिया।

स्वास्थ्य समिति की समीक्षा बैठक में राष्ट्रीय कार्यक्रमों की प्रगति पर जोर

श्रीकंचनपथ न्यूज

कोरिया। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के सभाकक्ष में बुधवार को प्रात: 11 बजे से जिला पंचायत सदस्य एवं स्वास्थ्य समिति की सभापति सुषमा कोराम की अध्यक्षता में स्वास्थ्य समिति की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. प्रशांत सिंह के मार्गदर्शन में जिले में संचालित सभी राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों की विस्तृत समीक्षा की गई।

बैठक में आगामी 13 जुलाई 2026 को कलेक्टर द्वारा आयोजित की जाने वाली समीक्षा बैठक को ध्यान में रखते हुए सभी अधिकारियों को गंभीरतापूर्वक तैयारी करने तथा राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों की शत.प्रतिशत उपलब्धि सुनिश्चित करते हुए संबंधित पोर्टलों में समय पर एवं शुद्ध जानकारी दर्ज करने के निर्देश दिए गए, ताकि वास्तविक प्रगति पोर्टल पर प्रदर्शित हो सके। बैठक में गर्भवती महिलाओं को समय पर गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने, मातृ मृत्यु दर में कमी लाने, नियमित प्रसव पूर्व जांच एवं टीकाकरण सुनिश्चित करने पर विशेष जोर दिया गया। साथ ही जन्म के समय शून्य डोज टीकाकरण, 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों के पूर्ण टीकाकरण, मौसमी बीमारियों की रोकथाम, आवश्यक दवाओं की पर्याप्त उपलब्धता तथा सतत क्षेत्रीय निगरानी बनाए रखने के निर्देश दिए गए। समीक्षा के दौरान आयुष्मान कार्ड, वय वंदना योजनाए कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम, टीबी 100 दिवसीय अभियान, एनसीडी कार्यक्रम के अंतर्गत शुगर, ब्लड प्रेशर एवं कैंसर स्क्रीनिंग, मलेरिया, फाइलेरिया सहित अन्य सभी राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों की प्रगति की विस्तार से समीक्षा की गई। बैठक में जिला अस्पताल के सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक डॉ. आयुष जायसवाल, जिला कार्यक्रम प्रबंधकअशरफ अंसारी, जिला नोडल अधिकारी एवं महामारी नियंत्रक डॉ. अभय जुगल तिर्की, बीईईए पटना के बीएमओ डॉ. श्रेष्ठ मिश्रा, सोनहत के बीएमओ डॉ. बलवंत सिंह, बचरापोड़ी के बीएमओ डॉ. अनित बख्ला, सभी विकासखंडों के कार्यक्रम प्रबंधक, सुपरवाइजर एवं स्वास्थ्य विभाग के अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।

किसानों के लिए मददगार विष्णु देव साय सरकारः रायगढ़ के 33 हजार किसानों को मिली 113.47 करोड़ रुपए की अग्रिम सहायता

82.19 करोड़ रुपए की अग्रिम कृषि सहायता और 31.28 करोड़ रुपए के खाद-बीज से खरीफ खेती को मिली नई रफ्तार

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार किसानों को खेती-किसानी के लिए हरसंभव सहयोग प्रदान करते हुए खेती को अधिक लाभकारी और सशक्त बनाने की दिशा में लगातार कार्य कर रही है। खरीफसीजन की शुरुआत में किसानों को आर्थिक संसाधनों की कमी का सामना न करना पड़े, इसके लिए कृषि आदानों की समय पर उपलब्धता सुनिश्चित की गई है।

इसी क्रम में रायगढ़ जिले के 33,017 किसानों को 79 प्राथमिक कृषि साख समितियों के माध्यम से 82.19 करोड़ रुपए की अग्रिम कृषि सहायता उपलब्ध कराई गई है। वहीं किसानों को 31.28 करोड़ रुपए मूल्य के खाद एवं बीज उपलब्ध कराए गए हैं। इस प्रकार जिले के किसानों तक अब तक 113.47 करोड़ रुपए की अग्रिम सहायता पहुंचाई जा चुकी है। समय पर मिली इस सहायता से किसानों को खेती की तैयारियों में बड़ी राहत मिली है और खरीफ फसलों की बुवाई को नई गति मिली है।

जिले के सभी विकासखंडों में किसानों को समान रूप से लाभान्वित किया गया है। रायगढ़ विकासखंड की 14 समितियों के माध्यम से 6,113 किसानों, पुसौर की 15 समितियों से 6,487 किसानों, खरसिया की 12 समितियों से 8,575 किसानों, धरमजयगढ़ की 15 समितियों से 4,898 किसानों, घरघोड़ा की 5 समितियों से 1,432 किसानों, तमनार की 10 समितियों से 3,228 किसानों तथा लैलूंगा की 8 समितियों से 2,284 किसानों को अग्रिम कृषि सहायता उपलब्ध कराई गई है। इससे किसानों को समय पर कृषि कार्य प्रारंभ करने के लिए आवश्यक संसाधन प्राप्त हुए हैं।

खरीफ सीजन में किसानों को उर्वरकों की कमी का सामना न करना पड़े, इसके लिए जिले की सभी सहकारी समितियों में पर्याप्त मात्रा में रासायनिक उर्वरकों का भंडारण किया गया है। विभागीय जानकारी के अनुसार जिले में लक्ष्य के विरुद्ध 22,668 मीट्रिक टन रासायनिक उर्वरकों का भंडारण किया गया है। इनमें से अब तक 18,641 मीट्रिक टन उर्वरकों का वितरण किया जा चुका है, जो निर्धारित लक्ष्य का लगभग 82 प्रतिशत है। किसानों को अब तक 10,718 मीट्रिक टन यूरिया, 2,342 मीट्रिक टन डीएपी, 2,430 मीट्रिक टन एनपीके, 795 मीट्रिक टन पोटाश तथा 2,356 मीट्रिक टन एसएसपी उपलब्ध कराया जा चुका है। सभी सहकारी समितियों में किसानों की मांग के अनुरूप उर्वरकों की सतत उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है, जिससे कृषि कार्य बिना किसी बाधा के संचालित हो रहे हैं।

पिछले सप्ताह हुई अच्छी वर्षा से खरीफ सीजन की गतिविधियों ने रफ्तार पकड़ ली है। समय पर उपलब्ध कराई गई अग्रिम कृषि सहायता, खाद एवं बीज से किसानों को खेती की तैयारियों में किसी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ रहा है। जिलेभर में धान सहित खरीफ फसलों की बुवाई तेजी से जारी है और किसान पूरे उत्साह के साथ खेतों में जुटे हुए हैं।

लोक निर्माण विभाग के सचिव ने रेलवे ओवर-ब्रिज एवं रेलवे अंडर-ब्रिज कार्यों की समीक्षा की

अधिकारियों को बेहतर समन्वय से काम करने के दिए निर्देश

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। लोक निर्माण विभाग के सचिव मुकेश कुमार बंसल ने विभाग के सेतु परिक्षेत्र और रेलवे के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक लेकर प्रदेश में रेलवे ओवर-ब्रिज और रेलवे अंडर-ब्रिज के निर्माणाधीन एवं प्रस्तावित कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने मंत्रालय में हुई बैठक में रेलवे ओवर-ब्रिज और रेलवे अंडर-ब्रिज के कार्यों में तेजी लाने लोक निर्माण विभाग और रेलवे के अधिकारियों को बेहतर समन्वय से काम करने के निर्देश दिए।

उन्होंने कार्यस्थलों की बाधाओं को तत्परता से दूर कर अप्रारंभ कार्यों को जल्दी शुरू करने को कहा। लोक निर्माण विभाग के प्रमुख अभियंता श्री वी.के. भतपहरी और दक्षिण-पूर्व-मध्य रेलवे के बिलासपुर मुख्यालय के प्रधान मुख्य अभियंता अवनीश कुमार पाण्डेय भी समीक्षा बैठक में शामिल हुए।

लोक निर्माण विभाग के सचिव ने बैठक में विभागीय और रेलवे के अधिकारियों को आपसी समन्वय को और मजबूत करते हुए निर्माण कार्यों में किसी भी प्रकार की अनावश्यक देरी नहीं करने के निर्देश दिए। उन्होंने निर्माणाधीन परियोजनाओं के कार्यों में तेजी लाते हुए उन्हें शीघ्र पूरा करने को कहा, ताकि लोगों को जाम और रेलवे फाटकों पर होने वाली असुविधा से राहत मिल सके। इससे माल परिवहन भी अधिक सुगम और तेज होगा।

विभागीय सचिव ने नए आरओबी और आरयूबी के कार्यों को जल्द शुरू करने सभी आवश्यक प्रक्रियाएं पूरी कर बाधाओं का तत्काल निराकरण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कार्यस्थलों से अतिक्रमण हटाने, भूमि व्यपवर्तन, नामांतरण तथा भू-अर्जन जैसी प्रक्रियाओं को प्राथमिकता के साथ समयबद्ध ढंग से पूरा करने को कहा। उन्होंने कहा कि प्रगतिरत परियोजनाओं को शीघ्र पूर्ण कर प्रदेश में आवागमन को अधिक सुरक्षित, सुगम, सुव्यवस्थित और तेज बनाना राज्य शासन की प्राथमिकता में है।

श्री बंसल ने कार्यस्थलों पर यूटिलिटी शिफ्टिंग के कार्यों में भी तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि यूटिलिटी शिफ्टिंग में देरी के कारण निर्माण कार्यों में अनावश्यक विलंब नहीं होना चाहिए। उन्होंने प्रस्तावित परियोजनाओं के प्राक्कलन तथा ड्राइंग-डिजाइन तैयार करने के लिए जहां भी लोक निर्माण विभाग और रेलवे के अधिकारियों के संयुक्त निरीक्षण की जरूरत हो, वहां तत्काल संयुक्त निरीक्षण कर आवश्यक कार्यवाही पूर्ण करने को कहा।

उन्होंने रेलवे ओवर-ब्रिज और रेलवे अंडर-ब्रिज परियोजनाओं को शीघ्रता से पूर्ण करने नियमित और कड़ाई से मॉनिटरिंग के निर्देश दिए।

उन्होंने लोक निर्माण विभाग और रेलवे के अधिकारियों को हर तीन महीने में बैठक कर कार्यों की प्रगति का आकलन करने और लंबित मामलों का समयबद्ध निराकरण सुनिश्चित करने को कहा। लोक निर्माण विभाग के अपर सचिव एस.एन. श्रीवास्तव, सेतु परिक्षेत्र के मुख्य अभियंता एस.के. कोरी, अधीक्षण अभियंता डी.के. माहेश्वरी, दक्षिण-पूर्व-मध्य रेलवे के बिलासपुर मुख्यालय के मुख्य अभियंता मनोज कुमार सिंह, सीपीएम-बिलासपुर राजीव कुमार और सीपीएम-रायपुर तत्वदर्शी साहू भी बैठक में मौजूद थे।

मालविका मोहनन का बोल्ड लुक देख फैंस हुए लट्टू, एक्ट्रेस ने बिकिनी में ढाया कहर

अभिनेत्री मालविका मोहनन आज कल सोशल मीडिया पर छाई हुई है। उनके सोशल मीडिया पर छाने की वजह से उनकी खूबसूरत फोटोज जो आजकल इंटरनेट पर वायरल हो रही है। आपको बता दें कि मालविका मोहनन फैन्स की फेवरेट हीरोइन में से एक हैं।

मालविका इंटरनेट पर भी काफी सक्रिय रहती हैं और फैन्स को सरप्राइज करने का मौका नहीं छोड़ती हैं। अब अभिनेत्री ने बिकिनी फोटोज से सोशल मीडिया पर पर हंगामा मचा दिया है। अभिनेत्री मालविका ने सोशल मीडिया अकाउंट इंस्टाग्राम पर अपनी बिकिनी फोटोज साझा की हैं, जिसमें उनका बोल्ड लुक दिखा। पेस्टल कलर की बिकिनी में मालविका किलर लगीं।

बिकिनी को उन्होंने प्रिंटेड स्कार्फसे कवर किया हुआ था, जो ट्रॉपिकल लुक के लिए एकदम परफेक्ट है। नीले आसमान, रेत और पेड़ों के बीच मलाविका का हॉलिडे आउटफिट कम्फर्ट, एलीगेंस और मॉडर्न बीचवियर को दर्शाता है।

जब बात हॉलिडे ड्रेसिंग की आती है, मलाविका मोहनन को पता है कि बिना किसी दिखावे के स्टाइल कैसे बनाए रखना है। उनका लेटेस्ट बीच लुक फ्रेश, मिनिमल और लग्जरी आइलैंड गेटअवे के लिए एकदम सूट करता है। अभिनेत्री मलाविका मोहनन रेत पर पेस्टल टोन की सॉफ्ट बिकिनी में क्लासी लुक से ध्यान खींचती दिखीं। स्टाइलिंग को मिनिमल रखते हुए मलाविका ने अपने आउटफिट के साथ मेटालिक बैंगल्स का स्टैक पहना।

लंबे स्टेटमेंट इयररिंग, ओपन हेयर और लाइट मेकअप से उन्होंने अपना लुक कंप्लीट किया। उनका दमकता हुआ चेहरा धूप में और भी निखरा दिखा। फैन्स मालविका के बिकिनी लुक को परफेक्ट और क्लासी बता रहे हैं। फैन्स फायर इमोजी बनकर उनके बिकिनी लुक को एक नंबर बता रहे हैं। आपको बता दें कि मालविका मोहनन ने कई मूवीज में अभिनय कर चुकी हैं।

वर्कफ्रॉम होम या बारिश का जादू? नुसरत भरूचा का मजेदार पोस्ट हुआ वायरल

वर्कफ्रॉम होम के दौरान ध्यान भटकना आजकल लगभग हर किसी की कहानी बन चुकी है। लेकिन अभिनेत्री नुसरत भरूचा के लिए इसकी वजह कोई सोशल मीडिया या फोन नहीं, बल्कि मानसून का खूबसूरत नज़ारा है। हाल ही में अभिनेत्री ने अपने घर पर वर्कआउट करते हुए कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर साझा कीं, जिनमें उनकी फिटनेस के साथ-साथ बारिश से सराबोर खूबसूरत माहौल ने भी सबका ध्यान खींच लिया।

तस्वीरों में नुसरत व्हाइट स्पोर्ट्स टॉप, ब्राइट रेड शॉर्ट्स और मैचिंग स्नीकर्स पहने नजर आ रही हैं। वह डंबल्स के साथ एक्सरसाइज, स्क्वैट्स और स्ट्रेचिंग करती दिखाई दे रही हैं। वहीं कुछ तस्वीरों में वह अपनी बालकनी में खड़े होकर बारिश के मनमोहक नज़ारे का आनंद लेती भी नजर आ रही हैं। वैसे घर पर रहकर फिटनेस को प्राथमिकता देने के साथ उन्होंने एक बार फिर हेल्दी लाइफस्टाइल की झलक दिखाई है। हालांकि, इस पोस्ट की सबसे खास बात उसका कैप्शन है। मानसून के खूबसूरत मौसम और हरियाली से घिरे नज़ारों के बीच नुसरत ने मजाकिया अंदाज में लिखा, उन्होंने कहा था, वर्कफ्रॉम होम उनका यह कैप्शन साफ तौर पर इशारा करता है कि ऐसे सुहाने मौसम में काम पर ध्यान केंद्रित करना कितना मुश्किल हो जाता है।

पोस्ट में बालकनी से दिखता हराभरा नज़ारा, बादलों से घिरा आसमान और शांत वातावरण मानसून की खूबसूरती को और भी खास बना रहा है। यही वजह है कि नुसरत का यह पोस्ट उन लोगों से भी जुड़ गया जो घर से काम करते हुए अक्सर बारिश के मौसम में खिड़की या बालकनी की ओर खिंचे चले जाते हैं।

नुसरत भरूचा अपने सोशल मीडिया पर अक्सर अपनी रोजमर्रा की जिंदगी की झलकियां साझा करती रहती हैं। कभी फिटनेस, कभी फैशन, कभी ट्रैवल तो कभी पर्दे के पीछे के खास पलों से सजे उनके पोस्ट फैंस को काफी पसंद आते हैं। इस बार भी उनका यह हल्का-फुल्का और रिलेटेबल पोस्ट सोशल मीडिया पर लोगों का दिल जीत रहा है और याद दिला रहा है कि कभी-कभी काम के बीच कुछ पल प्रकृति का आनंद लेना भी जरूरी होता है।

ज्योति पूर्वज और पूर्वज अभिनीत सनसनीखेज विज्ञान-फाई थ्रिलर किलर का विशेष पोस्टर जारीं

ज्योति पूर्वज और पूर्वज अभिनीत सनसनीखेज विज्ञान-फाई थ्रिलर किलर उद्योग में महत्वपूर्ण चर्चा पैदा कर रही है। फिल्म में मनीष गिलाडा, चंद्रकांत कोल्लू, विशाल राज, अर्चना अनंत और गौतम चक्रधर कोप्पीशेट्टी भी प्रमुख भूमिकाओं में हैं।

पूर्वाज और ए. पद्मनाभ रेड्डी द्वारा थिंक सिनेमा और एयू एंड आई स्टूडियोज के बैनर तले और ध्यानम नन्नागारू के आशीर्वाद से निर्मित इस फिल्म को उर्वेश पूर्वाज ने प्रस्तुत किया है और इसका निर्देशन भी पूर्वाज ने ही किया है। व्यापक वीएफएक्स कार्य सहित संपूर्ण पोस्ट-प्रोडक्शन प्रक्रिया पूरी होने के बाद, फिल्म अब भव्य थिएटर रिलीज के लिए तैयार है।

बेहद प्रतिभाशाली अभिनेत्री ज्योति पूर्वाज के फिल्म निर्माताओं ने फिल्म का एक विशेष पोस्टर जारी किया। पोस्टर में ज्योति एक शक्तिशाली और रहस्यमयी सुपर शी के किरदार में नजर आ रही हैं, जिनका दमदार लुक सबका ध्यान खींच लेता है। उनकी इस आकर्षक उपस्थिति की तुलना एंजेलिना जोली के फिल्म मैलीफिसेंट के यादगार लुक से की जा रही है। ज्योति पूर्वाज का सुपर शी के रूप में अभिनय दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर देगा।

निर्देशक पूर्वाज किलर के साथ एक अविस्मरणीय सिनेमाई ब्रह्मांड का निर्माण कर रहे हैं। फिल्म के निर्देशन के अलावा, वे सीएनए एकीकरण और आरओवाई प्रोटोकॉल पर काम करने वाले एक वैज्ञानिक की भूमिका भी निभाएंगे, जिससे कहानी में एक और दिलचस्प मोड़ आएगा।

फिल्म की प्रगति के बारे में बात करते हुए निर्देशक पूर्वाज ने कहा

फिल्म किलर का पोस्ट-प्रोडक्शन कार्य पूरा हो चुका है। फिल्म में कई हाई-एंड वीएफएक्स शॉट्स होने के कारण इन्हें पूरा करने में थोड़ा अतिरिक्त समय लगा। अब सभी वीएफएक्स कार्य पूर्ण हो चुके हैं। साथ ही, व्यावसायिक बातचीत भी सुचारू रूप से चल रही है। कई प्रमुख वितरकों और खरीदारों ने हमारे निर्माताओं के साथ फिल्म देखी है और अंतिम परिणाम से प्रसन्नता व्यक्त की है। हम जल्द ही व्यावसायिक सौदे पूरे करेंगे, सेंसर की औपचारिकताएं पूरी करेंगे और किलर को भव्य थिएटर रिलीज के साथ दर्शकों तक पहुंचाएंगे।

'टॉक्सिक' का पहला गाना 'तबाही' हुआ रिलीज, कियारा और यश के बीच दिखी जबरदस्त केमिस्ट्री

साउथ सुपरस्टार यश की आगामी फिल्म 'टॉक्सिक' का पहला गाना 'तबाही' कुछ ही देर पहले कई भाषाओं में रिलीज कर दिया गया है। इस गाने में कियारा आडवाणी और यश की जबरदस्त केमिस्ट्री नजर आ रही है। निर्देशक गीतू मोहनदास की फिल्म 'टॉक्सिक: ए फेयरी टेल फॉर ग्रोन-अप्स' इस साल 26 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। फिल्म की रिलीज से पहले निर्माताओं ने इसका पहला गाना 'तबाही' आज रिलीज कर दिया है। इस गाने में कियारा आडवाणी और यश की सिजलिंग केमेस्ट्री नजर आ रही है।

कई भाषाओं में रिलीज हुआ गाना

'टॉक्सिक' का गाना 'तबाही' हिंदी सहित, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम भाषाओं में रिलीज किया गया है। 'तबाही' गाने को विशाल मिश्रा ने अपनी आवाज दी है। इसे राज शेखर ने लिखा है। इसका संगीत विशाल, बिटुपोन बोरुआ, कंदर्पा कलिता और त्रिहंगकु लहकर ने मिलकर तैयार किया है। इस गाने को यश और कियारा आडवाणी के ऊपर फिल्माया गया है।

कब रिलीज होगी टॉक्सिक

तमाम रिलीज डेट बदलने के बाद 'टॉक्सिक' को 26 अगस्त 2026 को दुनियाभर के सिनेमाघरों में रिलीज किया जाएगा। इस फिल्म का निर्देशन गीतू मोहनदास ने किया है। इस फिल्म में कियारा और यश के अलावा हुमा कुरैशी, नयनतारा, रुक्मिणी वसंत और तारा सुतारिया जैसे कई कलाकार अहम भूमिकाओं में नजर आएंगी।

कर्ली बालों की देखभाल के लिए खरीदते हैं प्रोडक्ट्स इन 5 बातों का रखें ध्यान

कर्ली बालों की देखभाल के लिए खास ध्यान देने की जरूरत होती है। जब आप कर्ली बालों के लिए प्रोडक्ट्स खरीदते हैं तो आपको कुछ बातों का खास ध्यान रखना चाहिए ताकि आपके बाल स्वस्थ और सुंदर दिखें। सही प्रोडक्ट्स का चयन करने से न केवल आपके बाल मजबूत होते हैं, बल्कि उनकी चमक भी बढ़ती है। आइए जानते हैं कि कर्ली बालों के लिए प्रोडक्ट्स खरीदते समय किन-किन बातों का ध्यान रखना चाहिए।

प्राकृतिक चीजों का चयन करें

जब भी आप कर्ली बालों के लिए कोई प्रोडक्ट खरीदें तो उसमें प्राकृतिक चीजें होनी चाहिए। हर्बल और प्राकृतिक सामग्रियां बालों को पोषण देती हैं और उन्हें स्वस्थ रखती हैं। केमिकल्स वाले प्रोडक्ट्स से बचें क्योंकि ये बालों को नुकसान पहुंचा सकते हैं और उनकी चमक को कम कर सकते हैं। प्राकृतिक चीजों वाले प्रोडक्ट्स आपके बालों को नमी प्रदान करते हैं और उन्हें टूटने से बचाते हैं।

नमी बहुत जरूरी है

कर्ली बालों को नमी की बहुत जरूरत होती है। इसलिए ऐसे शैंपू और कंडीशनर चुनें, जो आपके बालों को गहराई से नमी दें। बिना सल्फेट और पैराबेन वाले प्रोडक्ट्स का उपयोग करें ताकि आपके बाल मुलायम और चमकदार रहें। इसके अलावा नमी बनाए रखने के लिए हफ्ते में कम से कम एक बार हेयर मास्क का उपयोग करें। यह आपके बालों को पोषण देगा और उन्हें टूटने से बचाएगा।

हल्के तेलों का करें इस्तेमाल

हल्के तेल जैसे नारियल तेल या जोजोबा तेल आपके कर्ली बालों के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं। ये तेल बालों की जड़ों तक पहुंचकर उन्हें मजबूत बनाते हैं और उनकी चमक बढ़ाते हैं। रात को सोने से पहले इन तेलों की मालिश करें और सुबह धो लें। इससे आपके बाल मुलायम और चमकदार रहेंगे। इसके अलावा इन तेलों का नियमित उपयोग बालों की जड़ों को पोषण देता है और उन्हें टूटने से बचाता है।

सुलझाने के लिए सही ब्रश का उपयोग

कर्ली बालों को सुलझाने के लिए सही ब्रश का चयन करना बहुत जरूरी है। डिटैंगलिंग ब्रश या वाइड टूथ कॉम्ब आपके बालों को बिना टूटे सुलझा सकता है। गीले बालों पर हल्के हाथों से उपयोग करें ताकि बाल कमजोर न हों। इसके अलावा बालों को सुलझाने से पहले थोड़ा सा कंडीशनर लगाएं, इससे बाल आसानी से सुलझेंगे और उनकी चमक भी बढ़ेगी। नियमित उपयोग से आपके बाल मुलायम और स्वस्थ रहेंगे।

गर्मी से बचाव करें

गर्मी आपके कर्ली बालों के लिए सबसे बड़ा दुश्मन होती है। हेयर ड्रायर या स्ट्रेटनर का उपयोग करने से बचें क्योंकि ये आपके बालों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। अगर आपको बालों को सेट करना है तो पहले हीट प्रोटेक्टेंट स्प्रे लगाएं ताकि बाल सुरक्षित रहें। इसके अलावा गर्मी वाले उपकरणों का उपयोग कम से कम करें और प्राकृतिक तरीकों से अपने बालों को सुखाने की कोशिश करें। इससे आपके बाल स्वस्थ रहेंगे और उनकी चमक भी बढ़ेगी।

राघव जुयाल की फिल्म भाई तेरा स्टार है का टीजर जारी, 30 जुलाई को सिनेमाघरों में होगी रिलीज

राघव जुयाल अपनी सोलो फिल्म भाई तेरा स्टार है के जरिए सिनेमाघरों में आने को तैयार हैं। हाल ही में मोशन पोस्टर आया था। ज्यादा इंतजार न कराते हुए निर्माताओं ने इसका टीजर जारी कर दिया है। फिल्म में राघव अजय सिंह नाम का ऐसा किरदार निभा रहे हैं, जो दिन-रात सिर्फहीरो बनने का सपना देखता है। निर्देशन की कमान विवेक बी. अग्रवाल ने संभाली है। निर्माण ईस्टवुड पिक्चर्स और इंडियन स्टोरीज 2 के बैनर तले किया गया है।

टीजर की शुरुआत राघव के किरदार से होती है, जो खुद को रॉकिंग रिबेल सुपर अल्ट्रा फ्यूचर स्टार बताकर अपना परिचय कराता है। ये ऐसा किरदार हैं, जो हीरो बनने के लिए झूठ बोलने से नहीं कतराता और खुद को सुपरस्टार समझता है। कहानी बॉलीवुड और उसके पीछे छिपे संघर्षों से पर्दा उठाती है। फिल्म में निहारिका एनएम (यूट्यूबर), संजय कपूर, बरखा सिंह और चंदन रॉय सान्याल भी मौजूद हैं। यह 30 जुलाई, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।

राघव को पहचान टीवी शो डांस इंडिया डांस से मिली थी, जिसमें उन्होंने प्रतियोगी बनकर हिस्सा लिया। साल 2014 में फिल्म सोनाली केबल से अपना फिल्मी डेब्यू किया। इसके बाद रेमो डिसूजा की फिल्म एबीसीडी एबीसीडी 2 और स्ट्रीट डांसर में नजर आए। लक्ष्य लालवानी के साथ फिल्म किल (2023) में नकारात्मक और खूंखार किरदार निभाकर राघव ने खूब चर्चा बटोरी। उन्हें आखिरी बार वेब सीरीज बैड्स ऑफ बॉलीवुड (2025) में देखा गया था।

खास खबर

सरपंच ने पूरे गांव को दिखाई सौर ऊर्जा से आत्मनिर्भरता की राह

रायपुर। बदलाव की शुरुआत अक्सर एक कदम से होती है। राजनांदगांव जिल के डोंगरगढ़ विकासखंड की ग्राम पंचायत चैतूखपरी में यह कदम सरपंच मनोहर सिन्हा ने उठाया है। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत अपने घर की छत पर 3 किलोवाट का सोलर रूफ्टॉप प्लांट लगाकर वे गांव के पहले सौर ऊर्जा उत्पादक बन गए हैं। अब उनका घर पूरे गांव के लिए प्रेरणा का केंद्र बन गया है। करीब दो लाख रुपये की लागत वाले इस संयंत्र पर उन्हें केंद्र और राज्य सरकार से कुल 1.08 लाख रुपये की सब्सिडी मिलेगी, जबकि शेष राशि बैंक से आसान किस्तों में वित्तपोषित की गई है। पहले हर महीने 700 से 800 रुपये तक बिजली बिल भरने वाले मनोहर सिन्हा को अब उम्मीद है कि उनका बिजली खर्च लगभग शून्य हो जाएगा। इतना ही नहीं, अतिरिक्त बिजली उत्पादन से भविष्य में आर्थिक लाभ मिलने की संभावना भी है। सोलर प्लांट लगने के बाद गांव के कई लोग इसे देखने पहुंच रहे हैं और योजना की जानकारी ले रहे हैं।

मोर गांव मोर पानी अभियान बना जल संरक्षण की नई राह

रायपुर। विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन ग्रामीण के अंतर्गत मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर जिले में संचालित मोर गांव मोर पानी अभियान जल संरक्षण को जनभागीदारी से जोड़ते हुए ग्रामीण विकास का प्रभावी माध्यम बनकर उभर रहा है। अभियान के तहत जिले में 350 आजीविका डबरियों तथा 150 से अधिक सामुदायिक तालाबों का निर्माण, गहरीकरण एवं विकास किया गया है। इन कार्यों से वर्षा जल के संरक्षण, भू-जल पुनर्भरण और ग्रामीण क्षेत्रों में जल उपलब्धता सुनिश्चित करने की दिशा में उल्लेखनीय सफलता मिलने लगी है। जिले में मानसून के दौरान प्राप्त होने वाले वर्षा जल का अधिकतम संचयन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से निर्मित इन जल संरचनाओं से अब जल संरक्षण के सकारात्मक परिणाम दिखाई देने लगे हैं।

मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 से खगेन्द्र कश्यप को मिला नया राशन कार्ड

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में प्रदेश सरकार आम नागरिकों की समस्याओं के त्वरित एवं प्रभावी निराकरण के लिए लगातार प्रयासरत है। मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 इसी दिशा में नागरिकों और शासन-प्रशासन के बीच एक भरोसेमंद सेतु के रूप में कार्य कर रही है, जहां प्राप्त शिकायतों का समयबद्ध समाधान सुनिश्चित किया जा रहा है। इसी क्रम में जांजगीर-चांपा जिले के नवागढ़ विकासखंड अंतर्गत ग्राम कुकदा निवासी खगेन्द्र कुमार कश्यप की लंबे समय से लंबित राशन कार्ड संबंधी समस्या का सफलतापूर्वक समाधान किया गया। नया राशन कार्ड नहीं बनने के कारण वे सार्वजनिक वितरण प्रणाली सहित विभिन्न शासकीय योजनाओं के लाभ से वंचित हो रहे थे। समस्या के समाधान के लिए कश्यप ने मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत प्राप्त होते ही संबंधित विभाग ने मामले की जांच की।

तेन्दूपत्ता संग्राहकों के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए सरकार प्रतिबद्ध

621 समितियों के 7.14 लाख से अधिक संग्राहकों को मिलेगा 162.32 करोड़ रुपए का प्रोत्साहन पारिश्रमिक

श्रीकंचनपथ समाचार

रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने 7.14 लाख से अधिक तेन्दूपत्ता संग्राहकों को 162.32 करोड़ की प्रोत्साहन पारिश्रमिक (बोनस) राशि का वितरण किया है। राज्य में वर्तमान में तेन्दूपत्ता संग्रहण की दर को 4,000 रुपए से बढ़ाकर 5,500 रुपए प्रति मानक बोरा किया गया है, जिससे संग्राहक परिवारों को सीधा आर्थिक संबल मिल रहा है। तेन्दूपत्ता का संग्रहण दर 5,500 रुपए प्रति मानक बोरा होने से संग्राहक परिवारों को अतिरिक्त आय प्राप्त हो रही है।

वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री केदार कश्यप ने कहा है कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार तेन्दूपत्ता संग्राहकों, वनवासियों और आदिवासी परिवारों के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है।

सरकार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि जंगल से जुड़े प्रत्येक श्रमिक को उसके श्रम का उचित सम्मान मिले और पारिश्रमिक समय पर सीधे उसके बैंक खाते में पहुंचे।

संग्रहण पारिश्रमिक का समय पर ऑनलाइन भुगतान: वन मंत्री ने बताया कि सरकार ने संग्रहण सत्र 2026 में भी तेन्दूपत्ता संग्राहकों को समय पर भुगतान सुनिश्चित किया है। प्रदेश के लगभग 11.15 लाख संग्राहकों को 734.25 करोड़ रुपए की संग्रहण पारिश्रमिक राशि ऑनलाइन माध्यम से सीधे उनके बैंक खातों में हस्तांतरित की जा चुकी है। इससे लाखों वनवासी और ग्रामीण परिवारों को आर्थिक मजबूती मिली है।

पारदर्शी और तकनीक आधारित भुगतान व्यवस्था: केदार कश्यप ने कहा कि तेन्दूपत्ता प्रदेश के लाखों वनवासी परिवारों की आजीविका का प्रमुख आधार है। इसलिए राज्य सरकार संग्रहण से लेकर भुगतान तक पूरी व्यवस्था को पारदर्शी, समयबद्ध और तकनीक आधारित बना रही है, ताकि संग्राहकों को किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े।

वनवासियों की आय बढ़ाना सरकार की प्राथमिकता: वन मंत्री कश्यप ने कहा कि राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना सर्वोच्च प्राथमिकता है। तेन्दूपत्ता संग्राहकों को समय पर पारिश्रमिक और प्रोत्साहन राशि उपलब्ध कराना इसी सोच का परिणाम है। सरकार वनवासियों के हितों की रक्षा, उनकी आय में वृद्धि तथा वन आधारित आजीविका को और अधिक सशक्त बनाने के लिए निरंतर कार्य करती रहेगी।

वर्ष 2023 के प्रोत्साहन पारिश्रमिक का वितरण शुरू

वन मंत्री केदार कश्यप ने बताया कि विगत 3 जुलाई को सहकारिता सप्ताह एवं अंतरराष्ट्रीय सहकारिता दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय द्वारा वर्ष 2023 के तेन्दूपत्ता संग्रहण के प्रोत्साहन पारिश्रमिक वितरण का शुभारंभ किया गया। इसके तहत प्रदेश की 621 प्राथमिक लघु वनोपज सहकारी समितियों से जुड़े 7,14,446 तेन्दूपत्ता संग्राहकों को 162.32 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) के माध्यम से सीधे उनके बैंक खातों में भेजी जा रही है। भुगतान की प्रक्रिया तेजी से जारी है और शीघ्र पूरी कर ली जाएगी।

'मोर गांव मोर पानी 2.0' से सहेजी जा रही वर्षा की हर बूंद

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। छत्तीसगढ़ शासन की जल संरक्षण संबंधी प्राथमिकताओं को धरातल पर प्रभावी रूप से क्रियान्वित करते हुए बलरामपुर जिला 'मोर गांव मोर पानी अभियान 2.0' के माध्यम से जल सुरक्षा का सशक्त मॉडल बनकर उभर रहा है। कलेक्टर के मार्गदर्शन में जिले में वर्षा जल संरक्षण, भू-जल पुनर्भरण और प्राकृतिक संसाधनों के संवर्धन के लिए व्यापक स्तर पर कंटूर ट्रेंच निर्माण कार्य किए जा रहे हैं। यह अभियान जल संकट के स्थायी समाधान के साथ-साथ कृषि, पर्यावरण और ग्रामीण आजीविका को भी नई मजबूती प्रदान कर रहा है।

अभियान के तहत जिले के शंकरगढ़, कुसमी, राजपुर एवं रामचंद्रपुर विकासखंडों के पहाड़ी और ढलान वाले क्षेत्रों में वैज्ञानिक पद्धति से कंटूर ट्रेंच का निर्माण किया जा रहा है। इन संरचनाओं के माध्यम से वर्षा का पानी बहकर नष्ट होने के बजाय भूमि में समाहित हो रहा है, जिससे भू-जल स्तर में वृद्धि, मिट्टी के कटाव पर नियंत्रण तथा भूमि की उर्वरता का संरक्षण सुनिश्चित हो रहा है।

जिले में अब तक 2,500 कंटूर ट्रेंच का निर्माण पूर्ण किया जा चुका है, जिनके माध्यम से लगभग 40.08 लाख लीटर वर्षा जल का संचयन एवं भू-गर्भ में अवशोषण सुनिश्चित हुआ है। इससे आसपास के क्षेत्रों में कुओं, बोरवेल और अन्य जल स्रोतों के जलस्तर में सुधार की संभावना बढ़ी है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल और सिंचाई की उपलब्धता को दीर्घकालिक लाभ मिलेगा।

रिज टू वैली वाटरशेड अवधारणा के अनुरूप जिले में 10 कार्यों के अंतर्गत कुल 5,124 कंटूर ट्रेंच का निर्माण कराया जा रहा है। इस तकनीक के माध्यम से पहाड़ी क्षेत्रों से तेजी से बहने वाले वर्षा जल को छोटे-छोटे ट्रेंचों में रोककर भूमि के भीतर समाहित किया जाता है। इससे वर्षा जल का संरक्षण, मिट्टी का कटाव नियंत्रण, खेतों में लंबे समय तक नमी बनाए रखने तथा फसलों के लिए प्राकृतिक जल उपलब्ध कराने में उल्लेखनीय सफलता मिल रही है।

यह अभियान जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से निपटने की दिशा में भी महत्वपूर्ण साबित हो रहा है। भू-जल स्तर में सुधार से गर्मी के मौसम में जल संकट कम होगा, किसानों को सिंचाई के लिए पर्याप्त जल उपलब्ध होगा तथा ग्रामीण क्षेत्रों में पारंपरिक जल स्रोतों का पुनर्जीवन संभव होगा। इसके साथ ही हरित आवरण बढ़ाने, कृषि उत्पादन में वृद्धि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने में भी यह पहल महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।

छत्तीसगढ़ में जल संरक्षण को जनभागीदारी का अभियान बनाते हुए संचालित 'मोर गांव मोर पानी 2.0' भविष्य की जल सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में एक प्रभावी और अनुकरणीय मॉडल के रूप में स्थापित हो रहा है।

सेलो बोर और आधुनिक कृषि यंत्रों पर अनुदान से खेती बनी आसान

श्रीकंचनपथ समाचार

रायपुर। छत्तीसगढ़ शासन की किसान हितैषी योजनाओं के प्रभाव से प्रदेश के किसानों की खेती अब आधुनिक तकनीकों से जुड़ रही है। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई) तथा कृषि अभियांत्रिकी योजनाओं के माध्यम से किसानों को सिंचाई सुविधाओं और आधुनिक कृषि यंत्रों पर अनुदान उपलब्ध कराया जा रहा है। इससे खेती अधिक सुगम, वैज्ञानिक और लाभकारी बनने के साथ किसानों की आय में भी निरंतर वृद्धि हो रही है।

प्रदेशभर में कृषि विभाग द्वारा किसानों को सेलो बोर (बोरवेल), ट्रैक्टर एवं अन्य आधुनिक कृषि यंत्रों पर अनुदान प्रदान कर सिंचाई और मशीनीकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है। इन योजनाओं के माध्यम से वर्षा पर निर्भरता कम हो रही है तथा किसान वर्षभर खेती और उद्यानिकी फसलों का उत्पादन कर बेहतर आय अर्जित कर रहे हैं।

सरगुजा जिले के विकासखंड अंबिकापुर के ग्राम नावाबांध निवासी किसान मुकुल राजवाड़े का परिवार इन योजनाओं का सफल उदाहरण है। परिवार को राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत सेलो बोर की सुविधा तथा कृषि अभियांत्रिकी योजना के तहत ट्रैक्टर सहित विभिन्न आधुनिक कृषि यंत्रों पर अनुदान प्राप्त हुआ। इससे खेती के सभी कार्य समय पर होने लगे हैं और उत्पादन क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। किसान मुकुल राजवाड़े ने बताया कि पहले खेती पूरी तरह वर्षा पर निर्भर थी, लेकिन सेलो बोर स्थापित होने के बाद अब पूरे वर्ष सिंचाई उपलब्ध हो रही है।

कुपोषण मुक्त छत्तीसगढ़ की दिशा में अनूठी पहल: मुनगा पौधारोपण से घर-घर पहुंचेगा पोषण का संदेश

श्रीकंचनपथ समाचार

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के सुशासन और स्वस्थ छत्तीसगढ़ के संकल्प को साकार करने की दिशा में महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा पोषण संवर्धन को जनआंदोलन बनाने के लिए लगातार नवाचार किए जा रहे हैं।

इसी क्रम में महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े के आह्वान पर प्रदेशभर में कुपोषण और एनीमिया के विरुद्ध जनजागरूकता अभियान संचालित किया जा रहा है। बेमेतरा जिले में बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत आयोजित मुनगा पौधारोपण विथ सेल्फी अभियान ने पोषण, पर्यावरण संरक्षण और जनभागीदारी का प्रभावी संदेश दिया। बेमेतरा जिला प्रशासन और महिला एवं बाल विकास विभाग के संयुक्त प्रयास से महिला सशक्तिकरण केंद्र (हब), सेक्टर दाढ़ी-2 एवं सेक्टर कन्हेरा में अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान गंभीर कुपोषित बच्चों, गर्भवती महिलाओं तथा एनीमिक महिलाओं के 18 घरों में मुनगा के पौधे रोपे गए और परिवारों को पौधों की देखभाल एवं नियमित उपयोग के लिए प्रेरित किया गया।

मुनगा (सहजन) को सुपर फूड के रूप में जाना जाता है। इसकी पत्तियों, फलियों और फूलों में आयरन, कैल्शियम, प्रोटीन, विटामिन-ए, विटामिन-सी तथा अनेक सूक्ष्म पोषक तत्व प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। विशेषज्ञों के अनुसार इसका नियमित सेवन गर्भवती महिलाओं के पोषण स्तर में सुधार, एनीमिया की रोकथाम तथा बच्चों के शारीरिक एवं मानसिक विकास में सहायक होता है। इसी उद्देश्य से अभियान के दौरान हितग्राहियों को मुनगा के पोषण एवं औषधीय महत्व की विस्तृत जानकारी दी गई। अभियान को केवल पौधारोपण तक सीमित नहीं रखा गया, बल्कि विथ सेल्फी अभियान के माध्यम से लोगों को इस जनअभियान का सक्रिय सहभागी बनाया गया। इससे पौधों के संरक्षण और नियमित उपयोग के प्रति लोगों में सकारात्मक जागरूकता विकसित करने का प्रयास किया गया। विभाग का मानना है कि जब प्रत्येक परिवार अपने घर में पोषण देने वाले पौधे लगाएगा और उनका उपयोग करेगा, तब कुपोषण और एनीमिया जैसी समस्याओं पर प्रभावी नियंत्रण संभव होगा।

महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े ने कहा है कि कुपोषण के खिलाफ लड़ाई केवल सरकारी योजनाओं से नहीं, बल्कि जनभागीदारी और जागरूकता से जीती जा सकती है। स्थानीय स्तर पर उपलब्ध पौष्टिक खाद्य संसाधनों का अधिकतम उपयोग कर बच्चों, किशोरियों और माताओं को बेहतर पोषण उपलब्ध कराया जा सकता है। इसी सोच के साथ प्रदेश में ऐसे नवाचारों को प्रोत्साहित किया जा रहा है।

कार्यक्रम में सेक्टर सुपरवाइजर, मिशन शक्ति की जेंडर विशेषज्ञ, सखी वन स्टॉप सेंटर की केंद्र प्रशासक, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता तथा महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित रहे।

जल संरक्षण और विकसित भारत पंचायत प्लान की दी गई जानकारी

जशपुर की सभी ग्राम पंचायतों में रोजगार दिवस एवं आवास दिवस का सफल आयोजन

श्रीकंचनपथ समाचार

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में ग्रामीण विकास एवं रोजगार सृजन को गति देने के उद्देश्य से जशपुर जिले की सभी ग्राम पंचायतों में रोजगार दिवस एवं आवास दिवस का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया। कार्यक्रमों में जनप्रतिनिधियों, ग्राम पंचायत सचिवों, रोजगार सहायकों, तकनीकी सहायकों, विभिन्न विभागों के अधिकारियों-कर्मचारियों तथा बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया।

रोजगार दिवस के दौरान ग्रामीणों को विकसित भारत रोजगार एवं आजीविका गारंटी मिशन के तहत रोजगार की मांग, समयबद्ध रोजगार उपलब्ध कराने की व्यवस्था, मजदूरी भुगतान की प्रक्रिया तथा श्रमिकों के अधिकारों की विस्तृत जानकारी दी गई। साथ ही मिशन के अंतर्गत लागू नई 300 रुपये प्रतिदिन की मजदूरी दर के बारे में जानकारी देते हुए अधिक से अधिक श्रमिकों से रोजगार कार्यों में भागीदारी करने का आग्रह किया गया।

कार्यक्रम में जल संरक्षण एवं प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन से जुड़े कार्यों पर विशेष जोर दिया गया। ग्रामीणों को बताया गया कि तालाब निर्माण एवं जीर्णोद्धार, डबरी निर्माण, नाला उपचार, कंटूर ट्रेंच, सोख्ता गड्ढों का निर्माण, वृक्षारोपण तथा अन्य जल संरक्षण कार्यों को मिशन के तहत प्राथमिकता के साथ कराया जा रहा है। इन कार्यों से वर्षा जल संचयन, भू-जल संवर्धन, कृषि उत्पादन में वृद्धि तथा ग्रामीणों की आजीविका को सुदृढ़ बनाने में मदद मिल रही है। इस अवसर पर विकसित भारत ग्राम पंचायत कार्यक्रम के अंतर्गत ग्राम पंचायत विकास योजना तैयार करने, ग्राम स्तरीय अभिलेख एवं एमआईएस अद्यतन करने, क्षमता विकास, कौशल उन्नयन, जनभागीदारी, स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण तथा सतत विकास संबंधी गतिविधियों की भी जानकारी दी गई। ग्राम पंचायतों को योजनाबद्ध, आत्मनिर्भर और विकासोन्मुख बनाने के लिए सभी हितधारकों की सक्रिय सहभागिता पर बल दिया गया।

आवास दिवस के अंतर्गत प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के हितग्राहियों को आवास निर्माण की प्रगति, जियो टैगिंग, निर्माण गुणवत्ता, किश्तों के भुगतान तथा निर्धारित समय-सीमा में आवास पूर्ण करने संबंधी आवश्यक जानकारी एवं मार्गदर्शन दिया गया। साथ ही अपूर्ण आवासों को शीघ्र पूर्ण कराने तथा पात्र हितग्राहियों को समय पर योजना का लाभ उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत अभिषेक कुमार ने कहा कि रोजगार दिवस एवं आवास दिवस का उद्देश्य केवल योजनाओं की जानकारी देना नहीं, बल्कि प्रत्येक पात्र परिवार तक शासन की योजनाओं का प्रभावी लाभ पहुंचाना है। उन्होंने कहा कि VB-GRAMG के तहत बढ़ी हुई 300 रुपये प्रतिदिन की मजदूरी से ग्रामीण श्रमिकों को आर्थिक मजबूती मिलेगी। जल संरक्षण कार्यों में जनभागीदारी से भविष्य की जल सुरक्षा, कृषि समृद्धि और सतत ग्रामीण विकास की मजबूत नींव तैयार होगी। उन्होंने अधिकारियों, कर्मचारियों, जनप्रतिनिधियों और ग्रामीणों से विकसित भारत पंचायत प्लान के सफल क्रियान्वयन में सक्रिय सहयोग देने का आह्वान किया।

वर्ष 2026 के लिए डॉक्टर खूबचंद बघेल कृषक रत्न पुरस्कार हेतु आवेदन आमंत्रित

बीजापुर । संचालनालय कृषि रायपुर द्वारा वर्ष 2026 में डॉक्टर खूबचंद बघेल कृषक रत्न पुरस्कार के लिए कृषकों से आवेदन पत्र आमंत्रित किए जा रहे हैं। कृषक आवेदन पत्र उपसंचालक कृषि व वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी कार्यालय से निःशुल्क प्राप्त कर सकते हैं। निर्धारित प्रपत्र अनुसार भरे गए आवेदन, आवश्यक दस्तावेजों के साथ उप संचालक कृषि व वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी कार्यालय में जमा कर सकते हैं साथ ही साथ आवेदन पत्र के साथ सफलता की कहानी प्रस्तुत करेंगे। कृषकों से आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 है अंतिम तिथि के बाद प्राप्त होने वाले आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा।

खास खबर

फार्म हाउस में चोरी करते दो भाई गिरफ्तार, 20 हजार का सामान और बाइक बरामद

जांजगीर-चांपा। जांजगीर-चांपा में फार्म हाउस में चोरी की वारदात का त्वरित खुलासा करते हुए दो सगे भाइयों को गिरफ्तार किया है। सारागांव निवासी पवन राठौर ने शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया कि एनएच-49 स्थित उनके निर्माणाधीन पेट्रोल पंप के सामने बने फार्म हाउस से सबमर्सिबल पंप, रॉड कटर मशीन, बिजली तार, सबमर्सिबल पैनल और प्लास्टिक चेयर सहित अन्य सामान चोरी हो गया था। पवन राठौर ने पुलिस को बताया कि 7 जुलाई की रात दो युवक स्प्लेंडर प्लस मोटरसाइकिल पर बोरी में सामान लेकर जाते दिखाई दिए। संदेह होने पर उन्होंने उनका पीछा किया और तत्काल पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही सारागांव पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए घेराबंदी कर दोनों आरोपियों को पकड़ लिया। जांच के दौरान फार्म हाउस के लोहे के दरवाजे की कुंडी टूटी हुई मिली, जिससे चोरी की पुष्टि हुई। पूछताछ में आरोपियों ने चोरी की वारदात स्वीकार कर ली। उनकी निशानदेही पर एक एचपी का सबमर्सिबल पंप, रॉड कटर मशीन, बिजली तार, सबमर्सिबल पैनल, दो प्लास्टिक कुर्सियां, बिना नंबर की स्प्लेंडर प्लस मोटरसाइकिल तथा चोरी में प्रयुक्त सब्बल बरामद किया गया। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान मुरलीडीह कंजी, थाना मुलमुला निवासी रमेश कुमार गोयल (29) और महेश गोयल (27) के रूप में हुई है। पुलिस ने दोनों के खिलाफ मामला दर्ज कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया।

तेज रफ्तार वाहन की टक्कर से कार चालक हुआ घायल आरोपी फरार

बिलासपुर। सिविल लाइन थाना क्षेत्र में बुधवार शाम तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने पीछे से कार को टक्कर मार दी। हादसे में कार चालक हिमांशु पाण्डेय (35) घायल हो गए, जबकि कार का पिछला हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। घटना के बाद आरोपी चालक वाहन सहित फरार हो गया। पुलिस के अनुसार मंगला स्थित महर्षि स्कूल रोड निवासी हिमांशु पाण्डेय शाम करीब 4.30 बजे साकेत विहार में एक वकील के पास दस्तावेज देने जा रहे थे। बलानी चौक स्थित शुभम विहार के पास उसलापुर की ओर से आए काले रंग के तेज रफ्तार वाहन ने उनकी कार को पीछे से टक्कर मार दी। घटना के बाद उन्होंने उज्ज्वल पाण्डेय के साथ सिविल लाइन थाने में शिकायत दर्ज कराई।

हाथियों ने 8 मकान तोड़े, 3 किसानों की फसल रौंदी

रायगढ़। जिले के धरमजयगढ़ वन मंडल में भोजन की तलाश में भटक रहे हाथियों ने ग्रामीण इलाकों में भारी तबाही मचाई है। बीते दो रातों के भीतर हाथियों के दल ने गांव के करीब पहुंचकर 8 ग्रामीणों के आशियाने उजाड़ दिए, वहीं 3 किसानों की खड़ी धान की फसल और थरहा (नर्सरी) को रौंद दिया। घटना की सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंच गई है और नुकसान का आकलन कर मुआवजा देने की कागजी कार्रवाई में जुट गई है। धरमजयगढ़ वन मंडल के कापू रेंज (लिसी बीट) के अंतर्गत आने वाले ग्राम चितामाड़ा, पखनाकोट और कमरई में सोमवार की रात हाथियों के दल ने जमकर उत्पात मचाया। यहां हाथियों ने ग्रामीण बैसाखु लकड़ा, संजय लकड़ा, दीपक केरकेट्टा, परमेश्वर मिंज, सिरिल मिंज और एक अन्य ग्रामीण के मकान को बुरी तरह क्षतिग्रस्त कर दिया। इसके बाद मंगलवार की रात को भी हाथियों ने पखनाकोट में ही भूखन मिंज और परसराम मिंज के मकानों को ध्वस्त कर दिया। मकानों को तोड़ने के साथ ही हाथियों ने रूपुंगा के दो किसानों कनकराम और गणेशराम के धान के थरहा (पौध) को पूरी तरह बर्बाद कर दिया।

भिलाई के होटल में म्यूजिक आर्टिस्ट की लाश मिली

रातभर शव के साथ कमरे में रही गर्लफ्रेंड, भाई बोला- सुसाइड नहीं, हत्या हुई

श्रीकंचनपथ न्यूज

भिलाई। छत्तीसगढ़ के भिलाई में एक होटल के कमरे में 19 साल के युवक की लाश मिली है। युवक का नाम शादाब बताया जा रहा है, जो म्यूजिक आर्टिस्ट था। शादाब मंगलवार शाम 4 साल बड़ी गर्लफ्रेंड के साथ होटल पहुंचा था। उसके दोस्तों को कॉल आया कि शादाब बेहोश हो गया है। उसके दोस्त और परिजन होटल पहुंचे। युवती ने दरवाजा खोला। दोस्तों और परिजनों ने देखा कि शादाब की बॉडी बेड पर पड़ी हुई थी। स्कार्फ का फंदा पंखे से लटका हुआ था। मामला सुपेला थाना क्षेत्र का है।

परिवार वालों ने लड़की पर युवक की हत्या का आरोप लगाया है। युवक के भाई ने कहा कि लड़की ने भाई को बेल्ट से मारा फिर खुद का हाथ और गर्दन ब्लेड से काटकर उसे धमकाया। भाई की हत्या के बाद लड़की बॉडी के साथ रात भर रही।

एक्स गर्लफ्रेंड से लंबे समय से बातचीत बंद थी। जिस दिन शादाब होटल में था, उसी दिन उसकी एक्स गर्लफ्रेंड का फोन आया था। इसे लेकर शादाब की गर्लफ्रेंड नाराज हो गई। फिर दोनों के बीच में लड़ाई हुई थी।

पुलिस के अनुसार, शुरुआती जांच में मामला आत्महत्या का लग रहा है। सूचना मिलते ही पुलिस होटल पहुंची और कमरे से शव को बाहर निकालकर पोस्टमॉर्टम के लिए सुपेला की मर्चुरी भेज दिया। फिलहाल, पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट का इंतजार है।

जानकारी के अनुसार, शादाब (19) जवाहर नगर, अटल आवास का रहने वाला था। म्यूजिक आर्टिस्ट था। पियानो बजाता था। वहीं, शादाब के परिवार वालों और उसके दोस्तों ने पुलिस की आत्महत्या की आशंका पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि शादाब के शरीर पर कई चोट के निशान मिले हैं।

परिवार का कहना है कि जिस हालत में उसका शव मिला, उसे देखकर आत्महत्या की बात पर यकीन करना मुश्किल है। उनका आरोप है कि शादाब की हत्या की गई है। उन्होंने पुलिस से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच करने की मांग की है। मृतक शादाब के भाई अल्ताफ शेख ने बताया कि उसका भाई करीब 6 महीने से भिलाई की युवती के साथ रिलेशनशिप में था। मंगलवार को शादाब और उसकी गर्लफ्रेंड कुणाल होटल गए थे। अल्ताफ शेख के मुताबिक, उन्हें भाई के दोस्तों से जानकारी मिली कि होटल में युवती के मौजूद रहने के दौरान सादाब की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। उन्होंने बताया कि रात करीब साढ़े 11 बजे सादाब के दोस्त होटल पहुंचे थे और उन्हें उस वक्त चेक आउट करना था, लेकिन कमरे का दरवाजा नहीं खुला।

दोस्तों ने करीब 2-3 घंटे तक इंतजार किया। उन्हें लगा कि दोनों कमरे में सो रहे होंगे। अल्ताफ के अनुसार, सुबह करीब 6 बजे युवती अकेले कमरे से बाहर निकली और कुछ देर बाद फिर कमरे में गई। अल्ताफने बताया कि सुबह करीब साढ़े 8 बजे शादाब के दोस्त दोबारा कमरे पर पहुंचे, लेकिन फिर भी दरवाजा नहीं खोला गया। बाद में जब दरवाजा खुला तो शादाब की बॉडी बेड पर पड़ी मिली। उन्होंने बताया कि वहां पंखे से स्कार्फबंधा हुई दिखाई दिया। भाई ने कहा कि उनका भाई सुसाइड जैसा कदम नहीं उठा सकता।

पुलिस बोली- मामले की जांच जारी

सुपेला थाना प्रभारी अंबर सिंह के मुताबिक मामले की हर पहलू से जांच की जा रही है। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट, फॉरेंसिक जांच और पूछताछ के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

बिना लाइसेंस और बिना पीओएस मशीन के उर्वरक बिक्री पर 79 बोरी उर्वरक जब्त

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। खरीफ सीजन के दौरान किसानों को गुणवत्तापूर्ण उर्वरक उचित मूल्य पर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जशपुर जिला प्रशासन द्वारा उर्वरकों की कालाबाजारी, जमाखोरी, नकली उर्वरकों की बिक्री एवं अनियमित विक्रय के विरुद्ध लगातार सख्त कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में विकासखंड बगीचा में बिना लाइसेंस एवं बिना पीओएस मशीन के उर्वरक विक्रय किए जाने के मामलों में कार्रवाई करते हुए कुल 79 बोरी उर्वरक जब्त कर उनके विक्रय पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया गया है।

उप संचालक कृषि के मार्गदर्शन में वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी लालसाय केरकेट्टा, कृषि विकास अधिकारी एवं उर्वरक निरीक्षक क्रुसलीना मिंज तथा ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारियों की टीम ने विकासखंड बगीचा के विभिन्न क्षेत्रों में निरीक्षण अभियान चलाया।

निरीक्षण के दौरान ग्राम सुलेसा में मनोज जायसवाल द्वारा बिना वैध लाइसेंस के उर्वरक विक्रय किया जाना पाया गया। उर्वरक (नियंत्रण) आदेश, 1985 के प्रावधानों के तहत कार्रवाई करते हुए 35 बोरी डीएपी, 10 बोरी सुपर फॉस्फेट तथा 7 बोरी यूरिया सहित कुल 52 बोरी उर्वरक जब्त कर उनके विक्रय पर रोक लगा दी गई।

इसी प्रकार सन्ना स्थित किसान कृषि केंद्र में बिना पीओएस मशीन के उर्वरक विक्रय किए जाने का मामला सामने आने पर 27 बोरी डीएपी उर्वरक जब्त कर बिक्री पर प्रतिबंध लगाया गया। अधिकारियों ने बताया कि दोनों प्रकरणों की विस्तृत जांच के बाद संबंधित दोषियों के विरुद्ध नियमानुसार पुलिस में प्राथमिकी दर्ज कराने सहित आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

उप संचालक कृषि ने बताया कि जिले के सभी विकासखंडों में जिला स्तरीय निगरानी दल द्वारा उर्वरक विक्रय केंद्रों का नियमित निरीक्षण किया जा रहा है। कालाबाजारी, जमाखोरी, नकली उर्वरकों की बिक्री अथवा निर्धारित मूल्य से अधिक दर पर विक्रय करने वालों के विरुद्ध उर्वरक (नियंत्रण) आदेश एवं प्रचलित नियमों के तहत कठोर कार्रवाई की जाएगी।

उन्होंने किसानों से अपील की कि वे केवल अधिकृत विक्रेताओं से पीओएस मशीन के माध्यम से ही उर्वरक खरीदें तथा किसी भी प्रकार की अनियमितता की जानकारी तत्काल कृषि विभाग को दें, ताकि समय पर प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके।

कोबरा-करैत और रसेल वाइपर ने 5 बच्चों को काटा, समय पर इलाज से सभी की जान बची

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायगढ़। रायगढ़ मेडिकल कॉलेज अस्पताल में अलग-अलग घटनाओं में विषैले सांपों के डंस का शिकार हुए पांच बच्चों का इलाज किया गया। इनमें किसी बच्चे को करैत, किसी को कोबरा और किसी को रसेल वाइपर ने काट लिया था। सभी की हालत गंभीर थी, लेकिन समय पर उपचार मिलने से उनकी जान बच गई। इलाज के बाद सभी बच्चों को बुधवार को स्वस्थ होने पर डिस्चार्ज कर दिया गया।

जानकारी के अनुसार, धरमजयगढ़ निवासी दो सगे भाई वीर कुमार (7) और लाकेश राठिया (12) को रात में सोते समय करैत ने गर्दन पर काट लिया था। सुबह तक दोनों के शरीर में जहर फैल चुका था और उनकी हालत गंभीर हो गई थी। वहीं, सक्ती जिले के हसौद निवासी मंजू (7) को कोबरा ने पैर में काट लिया था, जिससे उसके पैर में गंभीर सूजन और फफोले पड़ गए। रायगढ़ निवासी हितेश ढंगर (5) को रसेल वाइपर ने डंस लिया, जिससे शरीर में रक्तस्राव और खून के थक्के बनने की समस्या शुरू हो गई। कलमी निवासी हर्षित प्रजापति (7) को भी सोते समय करैत ने काट लिया था, जिससे उसकी हालत गंभीर हो गई। सभी बच्चों को अलग-अलग समय पर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया।

अस्पताल पहुंचने पर अधिकांश बच्चों में पलकें झुकना, बोलने और निगलने में कठिनाई, मांसपेशियों में कमजोरी, सांस लेने में दिक्कत जैसे गंभीर लक्षण दिखाई दे रहे थे। इनमें से तीन बच्चों को तत्काल पीआईसीयू में भर्ती कर वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया।

अस्पताल अधीक्षक डॉ. दुर्गा शंकर पटेल ने बताया कि विषैले सर्पदंश जैसे गंभीर मामलों में समय पर एंटी-स्नेक वेनम, वेंटिलेटर सुविधा और प्रशिक्षित चिकित्सकीय टीम की उपलब्धता के कारण पांचों बच्चों की जान बचाई जा सकी। उन्होंने बताया कि सभी उपचार और आवश्यक दवाएं आयुष्मान योजना के तहत पूरी तरह निशुल्क उपलब्ध कराई गईं।

रायपुर में दो बाइक चोरी का खुलासा, आरोपी गिरफ्तार, 1 लाख की 2 मोटरसाइकिल बरामद

रायपुर। न्यू राजेंद्र नगर निवासी सौरभ सिंह ठाकुर ने शिकायत दर्ज कराई थी कि 2 जुलाई की रात उन्होंने अपनी स्प्लेंडर प्लस घर के नीचे पार्क की थी। अगले दिन सुबह बाइक गायब मिली। मामले में अज्ञात चोर के खिलाफ केस दर्ज किया गया। इसी थाना क्षेत्र में अमलीडीह तालाब स्थित शीतला मंदिर के पास से रोहित कुमार रजक की सुपर स्प्लेंडर भी चोरी हो गई थी। इस मामले में भी न्यू राजेंद्र नगर थाने में एफआईआर दर्ज की गई थी।

दोनों मामलों की जांच के दौरान पुलिस ने घटनास्थल और आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले। मुखबिरों से मिली सूचना के आधार पर पुलिस ने निरमलेश तिवारी को हिरासत में लेकर पूछताछ की। पूछताछ में उसने दोनों बाइक

चोरी की वारदातों को अंजाम देना स्वीकार कर लिया। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से चोरी की दोनों मोटरसाइकिल बरामद कर ली हैं। जब्त वाहनों की कुल कीमत करीब 1 लाख रुपए बताई गई है।

गिरफ्तार आरोपी निरमलेश तिवारी (33) मूल रूप से मध्य प्रदेश के रीवा जिले के हनुमना थाना क्षेत्र के ग्राम डोल का रहने वाला है। वर्तमान में वह रायपुर के अमलीडीह स्थित सिंधु वाटिका में रह रहा था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है।

फोरेक्स ट्रेडिंग के नाम पर 74 लाख ठगने वाले गिरफ्तार

पुलिस ने रेड मारकर राजस्थान से 2 आरोपी पकड़े, टेलीग्राम ग्रूप से पीड़ितों को फंसाया था

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। ट्रेडिंग में मोटा मुनाफा कमाने का झांसा देकर 74 लाख रुपए की ऑनलाइन ठगी करने वाले दो अंतरराज्यीय साइबर ठगों को रायपुर पुलिस ने राजस्थान से गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने गूगल सर्च के जरिए पीड़ित को टेलीग्राम ग्रुप से जोड़कर निवेश के लिए उकसाया।

अलग-अलग किस्तों में 74 लाख रुपए ट्रांसफर कराने के बाद न तो मुनाफा दिया और न ही रकम लौटाई। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से वारदात में इस्तेमाल तीन मोबाइल फोन भी जब्त किए हैं।

पुलिस उपायुक्त (क्राइम एवं साइबर) स्मृतिक राजनाला और पुलिस उपायुक्त (पश्चिम) संदीप पटेल के निर्देश पर एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट और न्यू राजेंद्र नगर थाना पुलिस की संयुक्त टीम ने यह कार्रवाई की।

पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनमें राजस्थान के जयपुर निवासी 26 वर्षीय मुकेश कुमार मीणा और सीकर निवासी 24 वर्षीय संदीप कुमार शामिल हैं।

अप्रैल महीने में आरोपियों ने ठगे थे पैसे

पुलिस के मुताबिक, न्यू राजेंद्र नगर के बहादुर आर्य ने 17 अप्रैल 2026 को गूगल पर FOREX ट्रेडिंग सर्च किया था। इसके बाद उन्हें एक वेबसाइट जरिए FIRSTIFY टेलीग्राम ग्रुप से जोड़ दिया गया।

ग्रूप के सदस्यों ने अधिक मुनाफे का भरोसा देकर उन्हें और उनके भतीजे को निवेश के लिए तैयार किया। दोनों ने अलग-अलग किस्तों में कुल 74 लाख रुपए ट्रांसफर कर दिए, लेकिन बाद में आरोपियों ने संपर्क तोड़ दिया।

जांच के दौरान पुलिस ने मोबाइल नंबर, बैंक खाते, टेलीग्राम और व्हाट्सएप आईडी समेत अन्य डिजिटल जानकारी की जांच की। बैंक ट्रांजेक्शन और डिजिटल चेन एनालिसिस से आरोपियों की लोकेशन राजस्थान में मिली। इसके बाद पुलिस टीम ने वहां दबिश देकर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया।

आरोपियों ने ठगी करने की बात स्वीकारी

पूछताछ में आरोपियों ने अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर साइबर ठगी करने की बात स्वीकार की है। न्यू राजेंद्र नगर थाने में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 318(4) और आईटी एक्ट की धारा 66(D) के तहत मामला दर्ज है। पुलिस जब्त मोबाइल फोन और अन्य डिजिटल साक्ष्यों की जांच कर गिरोह के अन्य फरार सदस्यों की तलाश में जुटी है।

कोरबा में तेज रफ्तार ट्रेलर ने 6 मवेशियों को रौंदा, मौत

कोरबा। कोरबा के उरगा थाना क्षेत्र में गुरुवार सुबह एक तेज रफ्तार ट्रेलर ने 6 मवेशियों को रौंद दिया। इस हादसे में सभी मवेशियों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दो गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना कुदुरमाल भाटापारा स्थित धनराज पेट्रोल पंप के पास हुई।

जानकारी के अनुसार, गुरुवार सुबह ट्रेलर तेज गति से कुदुरमाल की ओर जा रहा था। धनराज पेट्रोल पंप के पास चालक सड़क किनारे खड़े और सड़क पार कर रहे मवेशियों के झुंड को देख नहीं पाया। ट्रेलर सीधे मवेशियों में घुस गया और उन्हें रौंदता चला गया।

टक्कर इतनी भीषण थी कि छह मवेशियों ने घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया। हादसे के तुरंत बाद आसपास के लोग मौके पर पहुंचे। ट्रेलर चालक गाड़ी लेकर भागने की

कोशिश करने लगा, लेकिन गुस्साए ग्रामीणों ने उसका पीछा कर उसे पकड़ लिया।

ड्राइवर को पुलिस के हवाले किया

ग्रामीणों ने चालक को उरगा पुलिस के हवाले कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही उरगा पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने मृत मवेशियों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया और घायल मवेशियों का इलाज शुरू कराया। हादसे के बाद घटनास्थल पर भारी भीड़ जमा हो गई। लोगों में ट्रेलर चालकों की लापरवाही और तेज रफ्तार को लेकर काफी नाराजगी देखी गई। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस मार्ग पर भारी वाहन अक्सर तेज गति से चलते हैं, जिससे आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं।

इस सड़क पर मवेशियों का जमावड़ा हमेशा लगा रहता है। कई बार तेज रफ्तार ट्रेलर और डंपर इनकी चपेट में आ जाते हैं, जिससे ऐसे हादसे होते हैं। ग्रामीणों ने प्रशासन से इस मार्ग पर भारी वाहनों की बेलगाम रफ्तार पर अंकुश लगाने की मांग की है। उन्होंने स्पीड ब्रेकर, साइन बोर्ड और ट्रैफिक पुलिस की तैनाती की भी अपील की।

ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि यदि समय रहते व्यवस्था में सुधार नहीं किया गया तो भविष्य में भी ऐसे हादसे होते रहेंगे।

नौकरी दिलाने का झांसा देकर 2.15 लाख की ठगी

श्रीकंचनपथ न्यूज

राजनांदगांव। बैंक में नौकरी दिलाने का झांसा देकर युवाओं से ठगी करने वाले दो आरोपियों को तुमड़ीबोड़ पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपियों को न्यायिक रिमांड में भेज दिया गया है।

पुलिस ने बताया कि ग्राम दिवानभेड़ी निवासी धनेश्वरी साहू ने शिकायत दर्ज कराई थी कि आरोपियों ने उनकी बेटी को छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक में सहायक प्रबंधक और बेटे को क्लर्क बनवाने का झांसा देकर कुल 1,15,000 रुपए की ठगी की। इसी तरह ग्राम डुमरडीह के हेमंत साहू ने अपने बेटे को एसबीआई में सहायक मैनेजर

बनाने के नाम पर 99,000 रुपए ठगने की शिकायत की। मामले की जांच के बाद ठगी के आरोपी मचानपार निवासी राहुल देशलहरे और अर्जुनी निवासी भागवत निषाद को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों से एक कार भी जब्त की गई है।

फंदे पर लटका मिला युवक, मौत के कारणों का पता नहीं

बिलासपुर। कोनी थाना क्षेत्र के देवनगर में बबलू तिवारी (32) का शव सोमवार शाम घर के आंगन में फंदे पर लटका मिला। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस के अनुसार बबलू अपनी पत्नी के साथ रहता था। सोमवार सुबह उसकी पत्नी काम पर चली गई थी, जबकि वह घर पर अकेला था। शाम करीब 4.30 बजे पत्नी लौटी तो उसने लोहे के एंगल से नायलॉन की रस्सी के सहारे बबलू को फंदे पर लटका देखा और पुलिस को सूचना दी। कोनी पुलिस ने पंचनामा कार्रवाई के बाद शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मंगलवार को पोस्टमार्टम कराया गया। पुलिस का कहना है कि प्रथम दृष्टया मामला फांसी का प्रतीत होता है, लेकिन मौत के वास्तविक कारणों का खुलासा नहीं हुआ है।

साय कैबिनेट की बैठक : लागू होगी बिजली भुगतान की नई व्यवस्था, मानसून सत्र के विधेयकों को भी मंजूरी

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में सरकार ने कई बड़े फैसले लिए हैं। बैठक में बिजली व्यवस्था को बेहतर बनाने भुगतान की नई व्यवस्था लागू करने पर सहमति बनी। विधानसभा के मानसून सत्र को देखते हुए सरकार ने कई महत्वपूर्ण विधेयकों के प्रारूप को भी मंजूरी दी है। इन विधेयकों को अब मानसून सत्र में पेश किया जाएगा। उद्योगों में निवेश बढ़ाने, कारोबार की प्रक्रिया आसान करने, जीएसटी से जुड़े नियमों में बदलाव और शिक्षा से जुड़े कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।

मंत्रिपरिषद् ने छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी द्वारा केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के विद्युत उपक्रमों से खरीदी जा रही बिजली के भुगतान की सुरक्षा के लिए वर्तमान त्रिपक्षीय अनुबंध **(Tripartite Agreement)** के स्थान पर भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुरूप डायरेक्ट डेबिट मैंडेट **(Direct Debit Mandate-DDM)** व्यवस्था लागू किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इस निर्णय से एनटीपीसी सहित अन्य सीपीएसयू से विद्युत आपूर्ति की निरंतरता सुनिश्चित होगी तथा भुगतान सुरक्षा की व्यवस्था आरबीआई के वर्तमान प्रावधानों के अनुरूप हो सकेगी।

इस निर्णय से राज्य शासन पर इससे कोई अतिरिक्त वित्तीय भार नहीं आएगा, क्योंकि वितरण कंपनी द्वारा भुगतान की व्यवस्था पूर्ववत रहेगी तथा आवश्यक होने पर पहले लेटर ऑफ क्रेडिट की व्यवस्था प्रभावी रहेगी। मंत्रिपरिषद की बैठक में छत्तीसगढ़ पुलिस विशेष कार्यपालिक बल (बस्तर फाइटर्स), फाइटर आरक्षक सेवा (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) नियम, 2026 में महत्वपूर्ण संशोधन को स्वीकृति दी गई है। मंत्रिपरिषद् द्वारा राजनांदगांव में 2000 सीट क्षमता वाले आधुनिक ऑडिटोरियम के निर्माण के लिए आवश्यक शासकीय भूमि के आबंटन का महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है।

मानसून सत्र के लिए इन विधेयकों को दी गई मंजूरी

मंत्रिपरिषद् द्वारा छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) (संशोधन) विधेयक, 2026 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया है। इस संशोधन में भारत सरकार के मंत्रिमंडल सचिवालय के विनियमन प्रकोष्ठ की अनुशंसाओं के अनुरूप निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना संबंधी प्रावधानों को अधिक व्यावहारिक, गुणवत्तापूर्ण और समकालीन बनाया गया है। इसके तहत निजी विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए विन्यास निधि के स्थान पर रक्षित निधि का प्रावधान लागू करने से अध्ययनरत छात्र-छात्राओं के भविष्य को संवारने के लिए आवश्यक उपाय सुनिश्चित किए जा सकेंगे। इसमें आधारभूत अधोसंरचना, पुस्तकालय एवं अन्य सुविधाओं को यूजीसी एवं सक्षम नियामक संस्थाओं के मानकों के अनुरूप सुनिश्चित करने का प्रावधान किया गया है। इस संशोधन से राज्य में गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा संस्थानों की स्थापना को प्रोत्साहन मिलेगा।

मंत्रिपरिषद् ने छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2026 के प्रारूप को मंजूरी दी है। इस संशोधन के माध्यम से छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर अधिकरण को समाप्त करने के साथ ही उससे संबंधित प्रावधानों में आवश्यक संशोधन किए जाएंगे। जीएसटी लागू होने के बाद वैट संबंधी द्वितीय अपीलों के मामलों में उल्लेखनीय कमी आई है और राज्य में जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण (त्रस्झ्झ्) की स्थापना भी हो चुकी है। ऐसे में पृथक वाणिज्यिक कर अधिकरण की आवश्यकता नहीं रह गई है। इस संशोधन के बाद अधिकरण में लंबित प्रकरणों का स्थानांतरण राजस्व मंडल को किया जाएगा, जिससे अपीलों के निराकरण की प्रक्रिया सुव्यवस्थित एवं अधिक प्रभावी हो सकेगी।

मंत्रिपरिषद की बैठक में छत्तीसगढ़ माल एवं सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2026 के प्रारूप को मंजूरी दी गई। इस संशोधन का उद्देश्य जीएसटी कानून को सरल बनाना, अनुपालन संबंधी प्रक्रियाओं को आसान बनाना तथा करदाताओं, विशेषकर निर्यातकों और इनवर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर वाले उद्योगों के लिए रिफंड प्रक्रिया को तेज और पारदर्शी बनाना है। इससे कर प्रशासन अधिक प्रभावी होगा, करदाताओं को सुविधा मिलेगी साथ ही राज्य के राजस्व में भी वृद्धि होगी।

मंत्रिपरिषद ने छत्तीसगढ़ औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन (संशोधन) विधेयक, 2026 के प्रारूप को मंजूरी दी है। इस संशोधन का उद्देश्य राज्य में निवेश को बढ़ावा देना, उद्योगों के लिए अधिक अनुकूल वातावरण तैयार करना तथा निवेशकों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना है। इस संशोधन विधेयक के प्रारूप को तैयार करने में अन्य अग्रणी राज्यों की औद्योगिक नीतियों का भी अध्ययन किया गया है। इससे निवेश प्रक्रिया अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनेगी और औद्योगिक विकास को नई गति मिलेगी।

मंत्रिपरिषद् की बैठक में छत्तीसगढ़ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस (विनिमय-मुक्ति एवं सुविधा) विधेयक, 2026 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया है। इस विधेयक का उद्देश्य राज्य में व्यापार और उद्योग स्थापित करने की प्रक्रियाओं को अधिक सरल, पारदर्शी, डिजिटल एवं समयबद्ध बनाना है। इस तरह का विधेयक लाने वाला छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य होगा। इसके अंतर्गत डीम्ड परमिशन , स्व-प्रमाणीकरण , तृतीय-पक्ष सत्यापन , जोखिम-आधारित निरीक्षण तथा दोहरे लाइसेंसिंग दायित्वों को समाप्त करने जैसे प्रावधान किए गए हैं। इससे निवेशकों के लिए अनावश्यक प्रक्रियात्मक बाधाएं कम होंगी, कारोबार करने में सुगमता बढ़ेगी तथा राज्य में निवेश, औद्योगिक विकास और रोजगार सृजन को नई गति मिलेगी।

मंत्रिपरिषद् ने नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण द्वारा आबंटित भूखंडों एवं निर्मित परिसरों पर देय ब्याज एवं अधिभार में राहत प्रदान करने हेतु वन टाइम सेटलमेंट योजना-2026 को मंजूरी दी है। इस योजना से पात्र आबंटितियों को निर्धारित शर्तों के तहत बकाया देयों के नियमितीकरण, परियोजनाओं को निर्धारित समयावधि में पूरा करने में मदद मिलेगी, जो विकास करने के इच्छुक है उनको अवसर मिलेगा और जो इच्छुक नहीं है, वे समय पर आबंटित भूमि को सरेंडर कर सकेंगे। इस निर्णय से मुकदमेबाजी में कमी आएगी, भूमि का बेहतर उपयोग सुनिश्चित होगा तथा नवा रायपुर में निवेश एवं विकास गतिविधियों को प्रोत्साहन मिलेगा।

मंत्रिपरिषद् ने जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) संशोधन अधिनियम, 2024 को छत्तीसगढ़ राज्य में अंगीकार करने के लिए विधानसभा में संकल्प प्रस्तुत किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है।

भारत सरकार द्वारा लाए गए इस संशोधन का उद्देश्य पर्यावरणीय कानूनों के अनुपालन को अधिक सरल, पारदर्शी और प्रभावी बनाना है। इसके तहत छोटे उल्लंघनों को अपराध की श्रेणी से हटाकर उन पर आर्थिक दंड का प्रावधान तथा दंड निर्धारण एवं अपील की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित किया गया है। इस निर्णय से राज्य में पर्यावरणीय नियमन को सरल बनाने, अनुपालन को प्रोत्साहित करने तथा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के साथ प्रभावी पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन स्थापित करने में सहायता मिलेगी।

मंत्रिपरिषद की बैठक में छत्तीसगढ़ भाड़ा नियंत्रण अधिनियम, 2011 (संशोधन) विधेयक, 2026 के प्रारूप को मंजूरी दी गई है। इसका उद्देश्य खाली मकानों को किराये पर देने को बढ़ावा देना और किरायेदारी से जुड़े विवादों का त्वरित समाधान सुनिश्चित करना है। इस संशोधन में भवन स्वामी और किरायेदार के अधिकार व दायित्व स्पष्ट किए गए है।

डीएमएफ योजना से किसानों को मिली आधुनिक खेती की सौगात

दंतेवाड़ा के 24 किसानों को वितरित किए गए पावर टिलर, खेती होगी आसान और कम खर्चीली

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। डीएमएफ (जिला खनिज संस्थान न्यास) योजना के तहत खनन-प्रभावित क्षेत्रों में किसानों को आधुनिक खेती, बेहतर सिंचाई और फसल भंडारण की सौगात मिल रही है। कृषि को उच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में शामिल कर कृषि अधोसंरचना और आजीविका को नई मजबूती दी जा रही है।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में किसानों को आधुनिक कृषि तकनीकों से जोड़ने और उनकी आय बढ़ाने के लिए विभिन्न योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन किया जा रहा है। इसी कड़ी में जिला खनिज संस्थान न्यास (डीएमएफ) योजना के तहत दंतेवाड़ा जिले के गीदम विकासखंड के 24 किसानों को पावर टिलर वितरित किए गए।

पावर टिलर वितरण कार्यक्रम में जिला पंचायत अध्यक्ष नंदलाल मुड़ामी ने किसानों को पावर टिलर की चाबी सौंपते हुए कहा कि आधुनिक कृषि यंत्रों के उपयोग से खेती आसान होगी, लागत कम आएगी, समय की बचत होगी और किसानों की आय बढ़ाने में मदद मिलेगी। उन्होंने किसानों से कृषि यंत्रों का बेहतर उपयोग कर आधुनिक खेती अपनाने की अपील की।

पावर टिलर एक बहुउपयोगी कृषि यंत्र है। इसका उपयोग खेत की जुताई, मिट्टी की गुड़ाई, मेड़ बनाने, बुवाई, खरपतवार नियंत्रण तथा अन्य कृषि कार्यों में किया जा सकता है। यह विशेष रूप से छोटे और मध्यम किसानों के लिए काफी उपयोगी है, जिससे कम समय और कम श्रम में खेती के कार्य पूरे किए जा सकते हैं।

कृषि विभाग के अधिकारियों ने बताया कि पावर टिलर के उपयोग से खेती की लागत कम होगी, श्रम की बचत होगी तथा कृषि उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि होगी। इससे किसानों की आय बढ़ाने में भी मदद मिलेगी। कार्यक्रम में जिला कृषि सभापति अध्यक्ष श्रीमती ममता मंडावी, जिला कृषि सभापति सदस्य श्रीमती किलेश्वरी नागेश, जनपद पंचायत अध्यक्षा श्रीमती शकुंतला भास्कर, जनपद उपाध्यक्ष दिनेश कौशल, जनपद कृषि सभापति मुन्ना राम कश्यप सहित अन्य जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे।

इस अवसर पर उप संचालक कृषि सूरज पंसारी, सहायक संचालक कृषि धीरज बघेल, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी किसान नेताम, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी (गीदम) श्री अशोक कुमार नेताम सहित कृषि विभाग के अधिकारी और ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी भी मौजूद रहे।

हरी खाद से कम होगी लागत और बढ़ेगी पैदावार

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। बढ़ती खेती लागत और घटती मिट्टी की उर्वरता के बीच हरी खाद किसानों के लिए नई उम्मीद बनकर सामने आई है। कृषि महाविद्यालय एवं अनुसंधान केन्द्र, रायगढ़ के वैज्ञानिकों का कहना है कि यदि किसान रासायनिक उर्वरकों पर पूरी तरह निर्भर रहने के बजाय हरी खाद और हरी पत्तियों की खाद को अपनाएं तो न केवल मिट्टी की सेहत सुधरेगी, बल्कि खेती भी अधिक लाभकारी बनेगी।

वैज्ञानिकों के अनुसार ढैंचा, सनई, मूंग, उड़द, लोबिया और ग्वार जैसी दलहनी फसलें 35 से 45 दिन बाद खेत में मिलाने से प्राकृतिक जैविक खाद में बदल जाती हैं। इससे प्रति हेक्टेयर 50 से 60 किलोग्राम तक नाइट्रोजन की पूर्ति होती है। वहीं नीम, करंज, ग्लिरिसिडिया और सहजन की हरी पत्तियां भी मिट्टी में जैविक तत्व और लाभकारी सूक्ष्मजीवों की सक्रियता बढ़ाती हैं।

इस प्राकृतिक तकनीक का सबसे बड़ा लाभ यह है कि रासायनिक उर्वरकों की जरूरत घटने से खेती की लागत कम होती है, जबकि फसलों की उपज में 15 से 20 प्रतिशत तक बढ़ोतरी देखी गई है। धान की गुणवत्ता में भी सुधार और पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ने के सकारात्मक परिणाम मिले हैं। वैज्ञानिकों ने किसानों से हरी खाद और ब्राउन मैन्योरिंग जैसी तकनीकों को अपनाकर मिट्टी की सेहत बचाने, पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने और टिकाऊ कृषि की दिशा में आगे बढ़ने की अपील की है।

प्रधानमंत्री आवास 2.0 लैंड टॉक्स फोर्स की बैठक सम्पन्न

पात्र आवासहीन परिवारों को पक्का घर मिले यह सुनिश्चित हो

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। मुख्य सचिव विकासशील की अध्यक्षता में यहां मंत्रालय महानदी भवन में प्रधानमंत्री आवास 2.0 भूमि टॉक्स फोर्स की बैठक सम्पन्न हुई। मुख्य सचिव ने अधिकारियों को प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 के अंतर्गत नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में आवासीय प्रोजेक्ट के लिए भूमि के सर्वेक्षण एवं चिन्हांकन करने के निर्देश अधिकारियों को दिए है।

मुख्य सचिव ने सभी जिलों के कलेक्टरों को प्रधानमंत्री आवास 2.0 के लिए हितग्राही की पहचान कर आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए है। उन्होंने आबादी भूमि पर रहने वाले पात्र हितग्राहियों को ढूंढकर सत्यापन करना एवं उन्हें आवास उपलब्ध कराने के लिए समूचित कार्यवाही करने के निर्देश दिए है।

मुख्य सचिव ने कलेक्टरों को नगरीय निकायों में वर्तमान और भविष्य की आवासीय आवश्यकता का आंकलन कर कार्ययोजना बनाने कहा है। जिससे समय पर हितग्राहियों को आवास उपलब्ध कराये जा सकें। इसी तरह से ग्रामीण क्षेत्रों में योजनांतर्गत हितग्राहियों की पहचान कर आवश्यकतानुसार आवास बनाने के लिए व्यापक कार्ययोजना बनाने के निर्देश दिए है। बैठक में नगरीय एवं प्रशासन विकास विभाग की सचिव आर.शंगीता, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग की सचिव शम्मी आबिदी, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के सचिव भीम सिंह सहित पंचायत एवं ग्रामीण विकास, नगरीय प्रशासन विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए।

सूखते हैंडपंपों के बीच फूटी अमृत धारा

रायपुर। धमतरी जिले का कुरूद विकासखंड,वह इलाका जो अपनी उपजाऊ जमीनों के लिए तो जाना जाता है, लेकिन गर्मियों के आते ही यहाँ की धरती पानी के लिए हांफने लगती थी। भूजल का अत्यधिक दोहन होने के कारण इसे 'सेमी-क्रिटिकल जोन' (भूजल संकट क्षेत्र) घोषित कर दिया गया था। हैंडपंप सूख रहे थे और घर की महिलाओं का आधा दिन दूर-दराज से पानी ढोने में ही बीत जाता था। अब, जल जीवन मिशन के तहत इस समस्या का एक बेहद आधुनिक और दूरदर्शी समाधान ढूंढ लिया गया है। मल्टी विलेज स्कीम इस क्षेत्र के लिए एक नई जीवनदायिनी बनकर उभर रही है।

मानसून के दौरान उद्योगों द्वारा किए जा रहे वृक्षारोपण कार्यों की हुई समीक्षा

हरित आवरण बढ़ाने के लिए उद्योगों को दिए गए महत्वपूर्ण निर्देश, 33 प्रतिशत क्षेत्र में ग्रीन बेल्ट विकसित करने पर जोर

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा मानसून 2026 के दौरान राज्य की औद्योगिक इकाइयों द्वारा संचालित वृक्षारोपण कार्यक्रमों की प्रगति की समीक्षा, समन्वय एवं आगामी कार्ययोजना के संबंध में राजधानी रायपुर स्थित न्यू सर्किट हाउस, सिविल लाइंस के न्यू कन्वेंशन हॉल में समीक्षा बैठक आयोजित की गई।

बैठक में छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल के सदस्य सचिव श्री राजू अगसिमनी ने उद्योगों द्वारा प्रस्तावित एवं संचालित वृक्षारोपण कार्यों की प्रगति, पौधों के संरक्षण एवं रखरखाव, निगरानी व्यवस्था तथा उद्योगवार कार्ययोजना की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने पर्यावरण संरक्षण के निर्धारित लक्ष्यों की समयबद्ध प्राप्ति के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश जारी करते हुए कहा कि वृक्षारोपण केवल लक्ष्य पूरा करने तक सीमित न रहे, बल्कि लगाए गए पौधों का संरक्षण एवं उनकी जीवित रहने की दर भी सुनिश्चित की जाए।

बैठक में उद्योगों को निर्देश दिए गए कि प्रत्येक हेक्टेयर क्षेत्र में न्यूनतम 2,500 पौधों का रोपण किया जाए तथा त्रि-स्तरीय (थ्री-लेयर) पौधारोपण को बढ़ावा देते हुए सघन ग्रीन बेल्ट विकसित की जाए। सभी औद्योगिक इकाइयों को अपने परिसर के कम से कम 33 प्रतिशत क्षेत्र में हरित क्षेत्र विकसित करने के निर्देश भी दिए गए। सदस्य सचिव ने बरगद, पीपल, नीम, आम सहित स्थानीय एवं पर्यावरण की दृष्टि से लाभकारी प्रजातियों के अधिकाधिक पौधे लगाने पर विशेष बल दिया। उन्होंने कहा कि औद्योगिक विकास के साथ-साथ पर्यावरणीय दायित्वों का निर्वहन भी समान रूप से आवश्यक है। उद्योगों को परिसर के भीतर एवं बाहर (इनडोर एवं आउटडोर) दोनों स्तरों पर वृक्षारोपण को बढ़ावा देने के लिए प्रेरित किया गया।

बैठक में पर्यावरणीय निगरानी व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने के निर्देश भी दिए गए। सभी उद्योगों को अपने ऑनलाइन सतत उत्सर्जन निगरानी प्रणाली (एनालाइजर) को 24 घंटे संचालित रखने तथा प्रत्येक तीन माह में उसका नियमित कैलिब्रेशन कराने के निर्देश दिए गए। बैठक में यह भी बताया गया कि शीघ्र ही विभागीय मंत्री ओ.पी. चौधरी राज्य के उद्योगपतियों के साथ बैठक कर वृक्षारोपण एवं पर्यावरण संरक्षण संबंधी कार्यों की समीक्षा करेंगे। बैठक में राज्य की प्रमुख औद्योगिक इकाइयों के अधिकृत प्रतिनिधि, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल के क्षेत्रीय अधिकारी एवं वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

डुमरतराई थोक बाजार से व्यापार एवं रोजगार दोनों को मिलेगा बढ़ावा - मुख्यमंत्री साय

डुमरतराई थोक बाजार फेस -2 का नामकरण लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर : परिसर में स्थापित होगी 15 फिट ऊंची प्रतिमा

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने रायपुर के डुमरतराई में छत्तीसगढ़ गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल द्वारा विकसित नवीन थोक बाजार फेस-2 का लोकार्पण किया। इस अवसर पर उन्होंने घोषणा की कि परिसर का नामकरण लौह पुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल के नाम पर किया जाएगा तथा यहां स्टैच्यू ऑफयूनिटी की तर्ज पर उनकी 15 फीट ऊंची प्रतिमा भी स्थापित की जाएगी।

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि सरदार वल्लभभाई पटेल ने देश को एक सूत्र में पिरोकर अखंड भारत की मजबूत नींव रखी। उनके नाम पर इस आधुनिक व्यापारिक परिसर का नामकरण राष्ट्र निर्माण में उनके अद्वितीय योगदान के प्रति हमारी विनम्र श्रद्धांजलि है। मुख्यमंत्री ने कहा कि व्यापार और रोजगार एक-दूसरे के पूरक हैं। जहां आधुनिक व्यापारिक अधोसंरचना विकसित होती है, वहां आर्थिक गतिविधियों का विस्तार होता है, नए निवेश आकर्षित होते हैं और रोजगार के अवसर भी बढ़ते हैं। डुमरतराई का यह आधुनिक थोक बाजार रायपुर सहित पूरे छत्तीसगढ़ के व्यापार को नई गति देगा तथा प्रदेश की अर्थव्यवस्था को और अधिक सशक्त बनाएगा।

उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय राजमार्ग-30 पर लगभग 36 एकड़ क्षेत्र में विकसित इस अत्याधुनिक परिसर में चौड़ी सड़कें, पर्याप्त पार्किंग, सुव्यवस्थित यातायात व्यवस्था तथा आधुनिक व्यापारिक सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। यह व्यापारियों की वर्षों पुरानी आवश्यकता को पूरा करने वाली महत्वपूर्ण परियोजना है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' के साथ-साथ 'ईज ऑफ लिविंग' को भी समान महत्व दे रही है। व्यापार, उद्योग और निवेश के अनुकूल वातावरण तैयार करने के लिए अनेक सुधार लागू किए गए हैं, जिनका सकारात्मक प्रभाव प्रदेश की अर्थव्यवस्था पर दिखाई दे रहा है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल अब केवल आवास निर्माण तक सीमित नहीं है, बल्कि प्रदेश की अधोसंरचना विकास परियोजनाओं में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। मंडल द्वारा अपनाई गई नई कार्यसंस्कृति और कुशल प्रबंधन विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण को नई गति देंगे।

आवास एवं पर्यावरण मंत्री ओ.पी. चौधरी ने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में प्रदेश में व्यापारिक अधोसंरचना का तेजी से विस्तार हो रहा है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2010 में डुमरतराई में आधुनिक थोक बाजार की जो परिकल्पना की गई थी, वह आज साकार हुई है। इससे व्यापारियों को आधुनिक सुविधाएं मिलने के साथ रायपुर की यातायात व्यवस्था भी अधिक सुगम होगी।

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल के अध्यक्ष श्री अनुराग सिंह देव ने कहा कि नवीन थोक बाजार मंडल की गुणवत्ता, नवाचार और जनसेवा के प्रति प्रतिबद्धता का उत्कृष्ट उदाहरण है। यह परियोजना प्रदेश में व्यापार, निवेश, रोजगार सृजन तथा समग्र आर्थिक विकास को नई गति प्रदान करेगी।

कार्यक्रम में कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार मंत्री गुरु खुशवंत साहेब, राज्यसभा सांसद लक्ष्मी वर्मा, विधायक मोतीलाल साहू, पुरंदर मिश्रा सहित जनप्रतिनिधि, विभिन्न व्यापारिक संगठनों के पदाधिकारी, व्यापारी एवं बड़ी संख्या में नागरिक उपस्थित थे।

उल्लेखनीय है कि डुमरतराई थोक बाजार का विकास दो चरणों में किया गया है। प्रथम चरण में लगभग 76 करोड़ रुपये की लागत से 536 व्यावसायिक दुकानें एवं हॉल निर्मित किए गए। द्वितीय चरण में लगभग 145 करोड़ रुपये की लागत से 154 स्वतंत्र व्यावसायिक दुकानों का निर्माण किया गया है। दोनों चरणों के पूर्ण होने के साथ प्रदेश को आधुनिक, सुव्यवस्थित और सर्वसुविधायुक्त थोक व्यापारिक परिसर की सौगात मिली है।

स्वत्वाधिकारी, मुद्रक, प्रकाशक राजेश अग्रवाल द्वारा मिशन मीडिया प्रा. लि. छत्तीसगढ़ भवन, प्रेस काम्पलेक्स, रजबंधा मैदान, रायपुर (छ.ग.) से मुद्रित कर, 204 आकाशगंगा सुपेला, भिलाई जिला दुर्ग (छ.ग.) से प्रकाशित। संपादक राजेश अग्रवाल shreekanchanpath2010@gmail.com, Mo - 9303289950